सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 245 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 18 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

सोनहत एनीकट निर्माण के लिए 3.49 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग ने कोरिया जिले के विकासखंड सोनहत में सोनहत एनीकट निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 49 लाख 48 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इस एनीकट के निर्माण से किसानों द्वारा स्वयं के साधन से लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिससे रबी और खरीफ फसलों की पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। इस योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को स्वीकृति दी गई है। एनीकट के बनने से क्षेत्र में भू-जल संवर्धन होगा। निस्तारी और पेयजल की सुविधा बेहतर होगी। साथ ही आवागमन भी सुगम होगा। किसानों को इसके निर्माण से लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

भिलाई में नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम लोकेश्वर देवांगन है जो की भिलाई तीन के उम्दा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रो लोकेश्वर खाना खाने के बाद अपने घर में ही था जिसके बाद वह अपने कमरे में चल गया लेकिन जब देर रात तक उसका दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों ने उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन कमरे के अंदर से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने फौरन इसकी सूचना डायल 112 को दी मौके पर पुलिस पहुंची और जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो लोकेश्वर फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने दरवाजा खोलकर उसके शव को नीचे उतारा और पीएम के लिए शास्त्री अस्पताल भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

चंबा में बोलेरो गाड़ी खाई में गिरी, सात लोगों की मौत

चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में वीरवार को चंबा-मसरूंड मार्ग पर छतरूंड के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोलेरो (एचपी-01सी-2581) में ग्राम महल पंचायत के सपरोठ गांव के छह लोग, जिनमें तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे और वाहन का चालक सवार था। ये सभी लोग काकड़ोथा गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान छतरूंड के पास अनियंत्रित होकर वाहन सड़क से लुढ़क गया और खाई में समा गया। खाई की गहराई लगभग 500 मीटर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। गहरी खाई से सभी सात शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की सेफ्टी देखेंगे केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत-माला परियोजना के तहत बन रहे रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की सेफ्टी जांचने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। एनएचएआई के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नितिन गडकरी जुलाई के शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री के दौरे को लेकर एनएचएआई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

बताया जा रहा है कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी रायपुर से विशाखापट्टनम तक बाय रोड सफर करेंगे। रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वे सड़क की क्वालिटी, सुरक्षा इंतजामों और कंस्ट्रक्शन स्पीड का लाइव जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे की संभावना को देखते हुए एनएचएआई के अफसरों ने रूट पर पैचवर्क, सफाई, साइन बोर्ड सुधारने और डिवाइडर चमकाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

आखिरी दौर में टनल का काम

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर की की शुरुआत 2020-21 में हुई थी। 16,482 करोड़ की लागत से इस बहुप्रतिक्षित कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण क्लीयरेंस में देरी के कारण यह प्रोजेक्ट थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन अब रफ्तार में है। फिलहाल कॉरिडोर का करीब 80त्न काम खत्म हो चुका है। अफसरों का दावा है कि टनल समेत बाकी पूरा हिस्सा इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का है।

रावघाट तक पूरा हुआ रेल ट्रैक, रेलवे ने पूरा किया ट्रायल रन, अब जल्द चलेगी यात्री ट्रेन

रेलवे स्टेशन व अन्य तकनीकी कार्य जोरों पर, जुलाई में रेलवे सेफ्टी टीम की जांच

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दल्लीराजहरा - रावघाट रेल परियोजना ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। रावघाट रेलखंड पर बुधवार को तकनीकी ट्रायल सफल रहा। परीक्षण के दौरान 58 बॉक्स एन वैगनों वाली मालगाड़ी रेक का उपयोग किया गया। यह ट्रायल आगे भी विभिन्न चरणों में जारी रहेगा, जिससे रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही रावघाट रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है।

बता दें कि लगभग 95 किलोमीटर लंबी दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना का विकास भारतीय रेलवे और सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। 2008 में हुए समझौता ज्ञापन के बाद प्रारंभ हुई यह परियोजना केवल लौह अयस्क परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर अंचल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाली परियोजना के रूप में उभरी है। परियोजना के तहत सेल द्वारा अब तक रेल लाइन निर्माण पर लगभग 1,800 करोड़ रुपये तथा रावघाट परियोजना के समग्र विकास पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरने के कारण इस परियोजना का निर्माण चुनौतीपूर्ण रहा है।

लंबे समय से इंतजार

रेलवे अधिकारियों के अनुसार विभिन्न गति और भार परिस्थितियों में परीक्षण सफल रहने व जरूरी अनुमतियां मिलने के बाद रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इस रेलखंड पर यात्री ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिसका बस्तर क्षेत्र के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

रावघाट परियोजना का अधिकांश काम पूरा हुआ

परियोजना के अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग एवं दूरसंचार प्रणाली से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार जुलाई 2026 के अंत तक स्टेशन परिसर के शेष कार्य भी पूरे होने की संभावना है। इसके बाद सेफ्टी कमीश्नर जांच करेंगे।

बढ़ेगा सुविधाओं का दायरा

वर्ष 2022 में दल्लीराजहरा से तरोकी तक यात्री रेल सेवा शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। रावघाट तक रेल पहुंचेगी तो इन सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्र देश व प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुडेंगे।

रायपुर में लगेगी डाक अदालत

- 29 जून को आयोजन, 24 जून तक दे सकेंगे आवेदन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। डाक सेवाओं से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर द्वारा 29 जून 2026 को परिमंडल स्तरीय 'डाक अदालत' का आयोजन किया जाएगा। यह डाक अदालत सोमवार को शाम 4 बजे रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित रायपुर प्रधान डाकघर (जनरल पोस्ट ऑफिस) भवन की द्वितीय मंजिल में आयोजित होगी।

डाक अदालत में डाक वस्तुओं के वितरण, काउंटर सेवाओं, लघु बचत योजनाओं, आवर्ती जमा (रिकरिंग डिपॉजिट), बचत बैंक खातों, बचत पत्रों, रजिस्ट्री, मूल्य देय पार्सल (वैल्यू पेयेबल पार्सल), एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनीऑर्डर, डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा से संबंधित शिकायतों की

सुनवाई कर उनका समाधान किया जाएगा।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय ने डाक उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनकी कोई शिकायत लंबित है तो वे उसका पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में 24 जून 2026 को दोपहर 2 बजे तक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमंडल, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त शिकायतों को इस डाक अदालत में शामिल नहीं किया जाएगा। डाक विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्रत्यक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि डाक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

बोरसी में रेलवे लाइन किनारे चला बुलडोजर हाईकोर्ट के आदेश पर चार दुकानें ढहाई

- 33 कब्जों को स्टे मिलने से कार्रवाई टली

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग नगर निगम ने गुरुवार सुबह बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमणों पर कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में चार दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण स्थलों पर नोटिस चस्पा किए। इसके बाद जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर अवैध निर्माणों को हटाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है।

यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद संभव हुई। पहले एसडीएम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने अपील दायर की थी। लगभग एक सप्ताह पहले एसडीएम न्यायालय ने इन अपीलों को खारिज कर दिया। वहीं, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुबह करीब 5 बजे से ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल, एसडीएम कार्यालय के अधिकारी और तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

37 निर्माण हटाने का आदेश, 33 को मिली राहत

अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट ने कुल 37 दुकानों और मकानों को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, इनमें से 33 प्रभावित पक्षों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया है। इस कारण फिलहाल उन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। चार ऐसे निर्माण थे जिनके पास किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं था। इसी वजह से नगर निगम ने उन्हीं चार दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। बाकी मामलों में न्यायालय के आगामी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जिन मामलों में न्यायालय से राहत नहीं मिली है, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि और रेलवे लाइन से लगे क्षेत्रों में अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला राज्यपाल रमेन डेका ने किया अभिनंदन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गुरूवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने गुरूवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के लोकभवन आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी बिड़ला का स्वागत किया।

संपादकीय

सुरक्षित सिरप

क्वालिटी कंट्रोल हेतु जरूरी डॉक्टर की पर्ची

भारत में छोटे-मोटे रोगों के उपचार के लिये मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाने की लोगों में आदत पायी जाती है। यह जाने बगैर कि घरेलू नीम-हकीमी जान को खतरे में भी डाल सकती है। भारत तथा कई अन्य देशों में देश में बने सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु से दवा उद्योग पर आंच आई थी। यही वजह है कि खांसी व अन्य दवाओं के सिरप की बिना डॉक्टर की पर्ची के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सरकार को लेना पड़ा है। निश्चय ही केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला सही समय पर लिया गया जरूरी कदम कहा जा सकता है। निस्संदेह, सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा माना जाना चाहिए। हाल की कुछ दुखद घटनाओं के घातक परिणामों के मद्देनजर लोगों को हर खांसी-जुकाम आदि छोटे-मोटे रोगों के लिये खुद दवा लेने की आदत से परहेज करना चाहिए। दरअसल, भारत में लंबे समय से ऐसी धारणा रही है कि ये सिरप आदि दवाइयां मौसमी बीमारियों के लिये नुकसान-रहित होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हुई दुखद घटनाओं ने इनके अंधाधुंध प्रयोग और दवा निर्माण से जुड़े कमजोर नियमन को ही उजागर किया है। सरकार को ये कदम अनेक दुखद घटनाओं के सामने आने के बाद उठाना पड़ा है, जब इन दवाओं के उत्पादन में गंभीर खामियां सामने आईं। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगाए गए थे कि गैम्बिया,उज्बेकिस्तान और कैमरून आदि देशों में दर्जनों बच्चों की मौत भारत में बने दूषित खांसी के सिरप के उपयोग से हुई थी। इतना ही नहीं, देश के भीतर भी दूषित दवाओं से जुड़ी मौतों की खबरों ने इन सिरपों की गुणवत्ता नियमन, परीक्षण और निगरानी पर गाहे-बगाहे सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से इन दुखद घटनाओं ने दुनिया भर में सस्ती दवाओं की आपूर्ति करने वाले भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान ही पहुंचाया है। सरकार की हालिया पहल को इसी दिशा में उठाया गए कदम के रूप में देखना चाहिए।

> “ निश्चय ही केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला सही समय पर लिया गया जरूरी कदम कहा जा सकता है। निस्संदेह, सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा माना जाना चाहिए। हाल की कुछ दुखद घटनाओं के घातक परिणामों के मद्देनजर लोगों को हर खांसी-जुकाम आदि छोटे-मोटे रोगों के लिये खुद दवा लेने की आदत से परहेज करना चाहिए। दरअसल, भारत में लंबे समय से ऐसी धारणा रही है कि ये सिरप आदि दवाइयां मौसमी बीमारियों के लिये नुकसान-रहित होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हुई दुखद घटनाओं ने इनके अंधाधुंध प्रयोग और दवा निर्माण से जुड़े कमजोर नियमन को ही उजागर किया है। सरकार को ये कदम अनेक दुखद घटनाओं के सामने आने के बाद उठाना पड़ा है, जब इन दवाओं के उत्पादन में गंभीर खामियां सामने आईं।

लेकिन सवाल सिर्फ कफसिरप का ही नहीं है। आम भारतीयों की आदत में शुमार है कि लोग अक्सर खांसी-बुखार की दवाइयां यह जाने बगैर सेवन करते हैं कि उनमें क्या-क्या मिला है। यह भी कि इनके उपयोग से हमारे शरीर में क्या-क्या साइड-इफेक्ट हो सकते हैं। यह भी जानने की कोशिश नहीं होती है कि इन सिरप आदि को अन्य दवाओं के साथ लेने से क्या-क्या नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे शरीर में हो सकती है। बहरहाल, अब जब सरकार ने तय कर दिया है कि अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ही सिरप आदि खरीदे जा सकते हैं तो मरीजों के तिमारदार तय कर सकेंगे कि किस कंपनी की गुण?वत्ता वाली दवा खरीदनी है। जिससे न केवल इलाज सही हो सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि मरीज के शरीर में कोई अन्य बीमारी छूट न जाए। लेकिन हकीकत यह भी है कि सिर्फ कठोर कानून बनाने मात्र से ही बेहतर परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते हैं। भारत में पहले से ही दवाइयों की बिक्री के नियमन से जुड़े कानूनों की कमी नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होने वाली दवाइयां अक्सर बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के ही आसानी से मेडिकल स्टोरों में मिल जाया करती हैं। दरअसल, असली चुनौती कानून का अनुपालन सख्ती से करने की होती है। जब तक देश में तमाम फार्मेसियों की नियमित जांच नहीं होती, कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान नहीं होता, तब नये नियम-कानून महज अच्छे इरादे वाले निर्देश मात्र बनकर रह जाएंगे। ऐसे में इस प्रयास का जमीनी असर बेहद कम ही रह पायेगा। वास्तव में देश में दवा उत्पादक इकाइयों की नियमित निगरानी, राज्यों में सशक्त ड्रग-कंट्रोल अथॉरिटी, नियमित गुणवत्ता जांच के अलावा जन चेतना अभियान चलाने की सख्त जरूरत है। लोगों को बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा लेने के खतरों से अवगत कराना होगा। निस्संदेह, सरकार द्वारा चिकित्सक के परामर्श पर ही सिरप आदि की उपलब्धता से जुड़े नियम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस सीमा तक एक जवाबदेह सिस्टम बना पाते हैं।

आकांक्षाओं का गणित: भारत में रोजगार का सवाल अब स्थिरता पर क्यों निर्भर है

डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

जब 1954 में सर आर्थर लुईस ने गरीब अर्थव्यवस्थाओं के अमीर बनने की परिघटना को समझाने का काम शुरू किया, तो उन्होंने विकास की मुख्य प्रक्रिया को पूंजी के संचय के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के जीवन-निर्वाह वाली खेती से हटकर अधिक कमाई वाले उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों की ओर मुड़ने के तौर पर पहचाना। उनका यह अनुमान बिल्कुल ही सही था कि यही बदलाव देर से औद्योगीकरण करने वाले हर देश का भविष्य तय करेगा। आज भारत ठीक इसी मोड़ पर खड़ा है और नीति-निर्माताओं के सामने सवाल पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने भर का नहीं है। बल्कि, उनके सामने इससे भी अधिक अहम सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी नौकरियां पैदा करने की स्थिति में है या नहीं जो पर्याप्त तादाद में हों, औपचारिक हों और एक युवा कामगार को जीवन भर बढ़ती उत्पादकता एवं सुरक्षा दे सकने लायक टिकाऊ हों।

इस जिम्मेदारी के भार को काफी सटीकता से बताया जा सकता है। 'आर्थिक समीक्षा 2023-24' ने 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे)' और आबादी से जुड़े अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि इस दशक की बाकी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को हर वर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजित करनी होंगी। यह आंकड़ा दो बढ़ते दबावों का नतीजा है: पहला, कामकाज के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ श्रमशक्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी; और दूसरा, संरचनात्मक बदलाव के कारण खेती से बाहर आने वाले कामगार। रोजगार में खेती की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 46 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तक इस हिस्सेदारी के घटकर एक-चौथाई तक आ जाने की संभावना है।

जुलाई 2025 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई और उसके अगले महीने से शुरू हुई 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' उस अंतर को पाटने की अब तक की सबसे सोची-समझी कोशिश है। इस योजना के तहत, जुलाई 2027 तक की दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने हेतु 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)' के जरिए 99,446 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। ईपीएफओ में पंजीकृत किसी कंपनी में पहली बार शामिल होने वाला और महीने में एक लाख रुपये से कम कमाने वाला कामगार, दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक पाने का हकदार बन जाता है। दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम (फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स) करने पर और बचत (सेविंग्स) के तौर पर मिलती है। वहीं, निर्धारित आधार-रेखा (बेसलाइन) से अधिक लोगों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को हर नए कामगार के लिए महीने में 3,000 रुपये तक मिलते हैं। ये शर्तें कुछ इस तरह तय की गई हैं कि छोटी कंपनियां भी इसके दायरे से बाहर हो जाने के बजाय इसमें शामिल हो सकें।

यह योजना भर्ती संबंधी सब्सिडी वाले आम व निराशाजनक तरीकों से इसलिए अलग और बेहतर है क्योंकि इसमें पहला लाभ मिलने से पहले छह महीने तक लगातार नौकरी करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार काम करने वाले को नौकरी पर रखने का लाभ तभी मिलता है जब वह कर्मचारी काम में कुशल बन जाए और टिका रहे। यह शर्त शुरुआती भर्ती को एक पक्की प्रतिबद्धता में बदल देती है, जिससे नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत वसूलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कर्मचारी को भी उतने महीने मिल जाते हैं जिनमें वह असली हुनर सीख सके ??और भरोसेमंद रिकॉर्ड बना सके। इस तरह, यह योजना केवल नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि कर्मचारी को बनाए रखने की अपेक्षाकृत अधिक कठिन प्रक्रिया के लिए पुरस्कृत करती है और इसके बाद कर्मचारी के पास रोजगार क्षमता एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसका वह कहीं भी सदुपयोग कर सकता है।

इस योजना का सबसे अधिक झुकाव मैन्यूफैक्चरिंग की ओर है, जहां नियोक्ता को मिलने वाला प्रोत्साहन दो वर्ष के बजाय चार वर्ष तक मिलता है। समय-सीमा को दोगुनी करने का यह निर्णय औद्योगिक क्षमता तैयार होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखकर लिया गया है। साथ ही, इससे निर्माता (मैन्यूफैक्चरर) समय से पहले स्वचालित व्यवस्था (ऑटोमेशन) लाकर कामगारों को हटाने के बजाय श्रमशक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं। अहम बात यह है कि सरकार ने इसे देश को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से जरूरी माना है। ईपीएफओ के जरिए, हर नए कामगार को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का पहली बार अहसास होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम कामगारों को यह सुरक्षा मिल पाती है। इस योजना के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद से लगभग 60 लाख नए कर्मचारी नामांकित हुए हैं। इनमें से अधिकतर 30 वर्ष से कम आयु के हैं और 18 लाख से अधिक महिलाएं हैं। वहीं, लगभग 1.77 लाख प्रतिष्ठानों ने 66 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इन प्रतिष्ठानों में कई ऐसी छोटी कंपनियां शामिल हैं, जहां लंबे समय से अनौपचारिक काम का बोलबाला रहा है।

हालांकि, एक अच्छी शुरुआत को पूरी तरह से सफल बदलाव मान लेना नासमझी होगी। इस योजना में धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को बाहर रखने, हर छह महीने में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के जरिए यह सुनिश्चित करना कि नौकरी सिर्फ कागजों के बजाय असल में बनी हुई है और भुगतान की स्वचालित प्रणाली जैसी कई अच्छी बातें हैं। ये सभी खूबियां इस बात को दर्शाती हैं कि योजनाकारों को इस बात का अहसास है कि ऐसी योजना में उन भर्तियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए जो अन्यथा भी हो जातीं। इसकी असली सफलता पहले वर्ष में नामांकित लोगों के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से पता चलेगी कि वे नौकरियां उस प्रोत्साहन के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती हैं या नहीं और इससे पैदा होने वाली मांग को पूरा करने के लिए काम के लायक युवा मौजूद हैं या नहीं। इसीलिए, इस योजना की सफलता कौशल को सिखाने में किए जा रहे निवेश से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि बेरोजगारी सिर्फ आमदनी से ही वंचित नहीं करती, बल्कि यह लोगों के हुनर, आत्म-सम्मान और समाज में उनकी हैसियत को भी कमजोर करती है। वोल्टेयर ने भी यही बात कही थी जब उन्होंने कैंडिड के जरिए यह निष्कर्ष दिया था कि काम करने से तीन बड़ी समस्याएं - बोरियत, बुराई और अभाव - दूर रहती हैं। इस तरह की योजना की अहमियत इसलिए है क्योंकि यह रोजगार के सही और संपूर्ण मतलब को समझती है। यह औपचारिक नौकरी को सिर्फ गिनती के आंकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि कामकाजी जीवन की पहली सुरक्षित सीढ़ी के तौर पर देखती है। अब जबकि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, तो चुनौती इस बात की है कि इस योजना में दिखाई गई धैर्य की भावना को बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि युवाओं को सार्थक रोजगार, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना के केन्द्र में रखा है, कुछ समय के प्रोत्साहन तक सीमित रहने के बजाय एक पूरी पीढ़ी के लिए टिकाऊ, उत्पादक और सम्मानजनक काम के रूप में मिले।

-लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।

न्याय के तराजू पर मशीनों की लाचारी

डॉ सुधीर कुमार

न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए हमें फॉरेंसिक मनोविज्ञान और 'व्यवहार विश्लेषण' पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जब जांच में मशीनी डेटा के साथ अनुभवी मनोवैज्ञानिक का विवेक जुड़ता है, तभी परिणाम अधिक विश्वसनीय, तर्कसंगत और मानवीय होते हैं। हाल ही में चर्चित हस्तियों और मीडिया जगत में 'नार्को टेस्ट' की मांग को लेकर छिड़ी बहस ने तकनीक की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। रौशन आनंद द्वारा खान सर (उर्फ फैजल खान) के संदर्भ में की गई नार्को टेस्ट की मांग, जन-मानस के उस भ्रम को दर्शाती है कि तकनीक ही अपराध का अंतिम समाधान है। लेकिन, न्याय के तराजू पर क्या मशीनें वास्तव में मानवीय सत्य को तोलने में सक्षम हैं?

हाल के वर्षों में निचली अदालतों ने हाई-प्रोफाइल मामलों में पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने में अत्यधिक सावधानी बरती है, जिसमें 'श्रद्धा वाकर हत्याकांड' भी चर्चा का विषय रहा। कानूनी जानकारों और अदालतों का स्पष्ट मत है कि पॉलीग्राफ से प्राप्त मशीनी डेटा 'साक्ष्य' नहीं, बल्कि केवल जांच को दिशा देने वाली 'सहायक सामग्री' है। भारत के 'आरुषि तलवार हत्याकांड' ने यह सिद्ध किया कि ऐसे परीक्षण वैज्ञानिक रूप से निर्णायक नहीं होते और इनके विरोधाभासी परिणाम जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा सकते हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन झूठ का नकाब ओढ़ना आसान है। अक्सर 'पॉलीग्राफ' को झूठ पकड़ने का अचूक हथियार माना जाता है, जबकि कानून और मनोविज्ञान के नजरिए से यह अत्यंत विवादास्पद है। मनोविज्ञान के अनुसार झूठ पकड़ना विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है; फिल्मों में पसीना आना या नज़रें चुराना झूठ की निशानी माना जाता है, पर असल जीवन में यह घातक हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे 'ओथेलो एरर' कहा जाता है - जहां एक निर्दोष व्यक्ति का स्वाभाविक डर, पसीना आना या घबराहट जांचकर्ताओं को 'झूठ' का प्रमाण प्रतीत होता है। याद रहे, मशीनें केवल शारीरिक तनाव को मापती हैं, मानवीय संवेदनाओं या सत्य को नहीं। 'कॉग्निटिव लोड' की पहचान केवल एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ का काम है, किसी जादुई मशीन का नहीं। ठीक यही स्थिति पूछताछ के दौरान होती है; एक निर्दोष व्यक्ति भी पुलिस के माहौल, पूछताछ के दबाव या अपनी प्रतिष्ठा खोने के डर से घबरा सकता है, पसीना छोड़ सकता है या उसकी हृदय गति बढ़ सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्ड्रिच एम्स (सीआईए अधिकारी एवं सोवियत जासूस) और 'बीटीके किलर' (डेनिस राडर) जैसे मामले यह स्पष्ट करते हैं कि पॉलीग्राफ परीक्षण पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हैं। एल्ड्रिच एम्स जैसे जासूसों ने तनाव नियंत्रित कर पॉलीग्राफको वर्षों तक छला, जबकि बीटीके किलर जैसे अपराधियों को डीएनए और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे ठोस साक्ष्यों ने ही बेनकाब किया। स्पष्ट है कि पॉलीग्राफ केवल एक 'संभावना' जता सकता है, निश्चितता नहीं। प्रशिक्षित अपराधी अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर काबू पाकर इन मशीनों को आसानी से विफल कर सकते हैं, अत: ये तकनीकें कभी भी सत्य का अंतिम पैमाना नहीं हो सकतीं।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पॉलीग्राफ नार्को-एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसे परीक्षण व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत प्राप्त 'आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार' का उल्लंघन माना है। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने या खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानूनन इन परीक्षणों के परिणाम सीधे 'साक्ष्य' नहीं माने जा सकते; इन्हें केवल जांच में दिशा देने वाले एक 'सुराग' के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है; विशेषकर डिजिटल युग में, जहां व्यक्तिगत डेटा और मस्तिष्क की निजता पर बड़ा संकट है, नार्को-एनालिसिस जैसे परीक्षणों को विज्ञान की आड़ में अनैतिक प्रयोग बनने से रोकना, न्यायपालिका की सर्वोपरि जिम्मेदारी है।

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इसे भ्रमित करने वाला मानकर खारिज किया है, तो इस्राइल में इसे दीवानी मामलों में अमान्य करार दिया गया है। यूरोप में इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों में इसकी भूमिका बेहद सीमित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन परीक्षणों में वैधता का अभाव है, जिसके कारण इन्हें अक्सर 'छद्म विज्ञान' की श्रेणी में रखा जाता है।

पॉलीग्राफमशीनों की बड़ी सीमा यह है कि वे 'सच' नहीं, केवल हृदय गति जैसे 'शारीरिक तनाव' को मापती हैं, जिसका कारण घबराहट या पुरानी यादें भी हो सकती हैं। यह एक 'फॉल्ट डिटेक्टर' है, न कि 'ट्रुथ डिटेक्टर', क्योंकि प्रशिक्षित अपराधी आसानी से अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर इसे विफल कर सकते हैं। अत: वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टि से ये मशीनें सत्य का अंतिम पैमाना नहीं हैं; इसके विपरीत, एक अनुभवी विशेषज्ञ ही अपराधी के उन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक संकेतों और व्यावहारिक बारीकियों को पकड़ सकता है, जिन्हें छिपाना लगभग असंभव होता है। मशीनों पर आंख मूंदकर विश्वास करना न्याय की मूल भावना के लिए खतरनाक है। हालांकि तकनीक जांच में एक उपयोगी 'सहायक' हो सकती है, लेकिन मशीनें मानवीय संवेदनाओं और जटिल परिस्थितियों को समझने में अक्षम हैं, इसलिए उन्हें 'अंतिम निर्णायक' नहीं माना जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए हमें फॉरेंसिक मनोविज्ञान और 'व्यवहार विश्लेषण' पर अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। जब जांच में मशीनी डेटा के साथ अनुभवी मनोवैज्ञानिक का विवेक जुड़ता है, तभी परिणाम अधिक विश्वसनीय, तर्कसंगत और मानवीय होते हैं।

यह समय जांच की मानवीय प्रणाली को उन्नत करने का है। यदि हम न्याय को केवल एक 'अल्गोरिद्म' के हवाले कर देंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब 'तथ्य' तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन 'न्याय' अपनी आत्मा खो देगा। एक मशीन यह तो बता सकती है कि अपराधी का हृदय कब और कितनी तेज़ धड़का, लेकिन केवल एक विवेकपूर्ण मस्तिष्क ही यह तय कर सकता है कि उस धड़कन के पीछे अपराध की ठंडी साजिश थी या मासूमियत का भय।

- लेखक कुरुक्षेत्र वि.वि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

वेतन से आगे: विकसित भारत के लिए कुशल कार्यबल की तैयारी

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

कोयंबटूर में काम करने वाले युवा रवि को, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई में अपनी पहली औपचारिक नौकरी के छह महीने पूरे कर चुके हैं और हाल ही में अपनी मासिक तनख्वाह के अलावा उन्हें बैंक खाते में 7,500 रुपये मिले। लगातार छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम अपने आप जारी कर दी गई। इससे पहले उनका परिवार सिर्फ़ अनौपचारिक काम करता था, जिसमें कोई अनुबंध, भविष्य निधि में योगदान या नौकरी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। यह पहला मौका था, जब उनकी नौकरी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया और उन्हें इस तरह का लाभ मिला।

रवि को मिली यह धनराशि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के 'भाग' के तहत मिली पहली किस्त है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोज़गार और कौशल पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस प्रावधान के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 15,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है। यह रकम दो किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने के बाद। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को ईपीएफओ ??पोर्टल के ज़रिए वित्तीय साक्षरता का कोर्स पूरा करना होगा और यह राशि बचत के एक साधन में जमा की जाएगी, ताकि कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रवि के लिए, ये छह महीने सिर्फ़ योग्यता हासिल करने का समय नहीं थे। ये वो वक्त था, जिसमें उन्होंने अपने काम की जगह को समझा, अपने काम से जुड़ी बुनियादी कौशल और योग्यता सीखी और अपने लिए रोज़गार का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं था।

यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम-वीबीआरवाई के भाग क्र में प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरुआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे-धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। इस शुरुआती लागत को कम करके यह प्रावधान, योजना का दायरा रवि जैसे लोगों को काम पर रखने वाले छोटे व्यवसायों तक बढ़ाता है। उसकी जैसी विनिर्माण इकाईयों के लिए, चार साल की अवधि, जो सामान्य अवधि से दोगुनी है, कंपनियों को ऑटोमेशन में निवेश के साथ-साथ अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ता कार्यबल 2047 तक 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने के लिए रोज़गार-आधारित विकास के ज़रिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है। कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोग किस सीमा तक औपचारिक रोज़गार में आते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुरक्षा मिलती है, यह इस बात पर भी असर डालेगा कि परिवारों और समुदायों में विकास का लाभ कैसे मिलता है। पीएम-वीबीआरवाई का मकसद 'स्वतंत्र भारत' से 'समृद्ध भारत' तक के सफ़र को मज़बूत करना है और दो साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

इस योजना की शुरूआत से, 60 लाख नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से 43.26 लाख (लगभग 71त्न) 18 से 30 साल की उम्र के हैं और 18.04 लाख (लगभग 30त्न) महिलाएं हैं, जो पहली बार औपचारिक रोज़गार से जुड़ी हैं। ये कर्मचारी विशेष सेवाओं, इंजीनियरिंग, व्यापार, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि कई तरह के औपचारिक संस्थानों में इसे अपनाया गया है।

सिर्फ़ प्रोत्साहन राशि के अलावा, पीएम-वीबीआरवाई से रवि को एक ईपीएफओ खाता और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला है। इससे वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो भविष्य निधि योगदान, बीमा सुरक्षा और कानूनी रोज़गार लाभ भी देता है। उनके जैसे पहली बार औपचारिक रोज़गार पाने वाले कई लोगों के लिए, यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज और एक व्यवस्थित रोज़गार से जुड़ने का एक बेहतर मौका है। लगातार छह महीने तक नौकरी करने की शर्त का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के तहत बनी नौकरियां असल करियर की नींव बनें। लंबे समय तक औपचारिक रोज़गार से कई क्षेत्रों में नौकरियों में काम आने वाला कौशल विकसित होता हैं, पेशेवर तौर-तरीके सीखने को मिलते हैं और भविष्य में नौकरी पाने की क्षमता भी मज़बूत होती है। इससे मिलने वाले फ़ायदे योजना के तहत मिलने वाली मदद की अवधि के बाद भी बने रहते हैं।

लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं।

काले मेघा पानी दे दो

काले मेघा पानी दे दो,
सबकी दुआएं ले लो,
वसुधा के आँचल से,
कष्ट सभी हरना।।।।
माटीपुत्र हलधर,
खेत सारे जोतकर,
फसल उगाने हेतु,
धरा बीज धरना।।।।
जलधार घनघोर, जलमग्न
ओर-छोर,
सूखे सभी जलस्रोत,
लबालब भरना।।।।
सुषमा' सुंदर सृष्टि, समुचित
जल वृष्टि,
खेतों में हो हरियाली,
शैल झरे झरना।।।।

प्रथम हो बरसात,
निकलते साथ-साथ,
साँप-बिच्छू घूमें पर,
आप नहीं डरना।।।।

रक्षित हों हर प्राणी,
ईश्वर ने रचा जिन्हें,
सोचें भी न अनुचित,
हमें जब तरना।।।।
छेड़ो नहीं जब तक,
काटते न तब तक,
मार कर जीव-जन्तु,
पाप नहीं करना।।।।
ईश्वर का उपहार,
मिलजुल उपचार,
जीवन प्रक्रिया चक्र,
सुखद विचरना। ।।।

कवयित्री सुषमा प्रेम पटेल
(रायपुर छ.ग.)

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

दुर्ग की छात्राओं ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा

दुर्ग। गीतांजलि संगीत महाविद्यालय की छात्राओं ने देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य, संगीत एवं कला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया। कत्थक रॉकर्स एन युनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डान्स के तत्वावधान में हुए आयोजन में जूनियर समूह की डिंपल मार्कंडेय, उत्सवी पटेल, नविष्ठा ठाकुर और स्वरा गजभिये ने विधि इंगले के मार्गदर्शन में कत्थक और भरतनाट्यम का मिश्रित नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे प्रतियोगिता की विशेष प्रस्तुति के रूप में सराहना मिली। वहीं जूनियर श्रेणी में आरना देशमुख ने एकल कत्थक नृत्य में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्था अध्यक्ष रत्ना नारमदेव ने कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की मेहनत और प्रशिक्षण का परिणाम है। प्राचार्य वीएन भोले ने विजेताओं को बधाई देते हुए आगे भी निरंतर साधना करने का संदेश दिया।

महाराजा दाहिर सेन को सिंध ब्रादर मंडल ने दी श्रद्धांजलि

भिलाई। आदर्श सिंध ब्रादर मंडल ने चंड्र दिवस और सिंध की सीमाओं के रक्षक महाराजा दाहिर सेन के 1314वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया। महाराजा दाहिर सेन की जीवनी पर प्रकाश डालकर उनके समर्पण की भांति राष्ट्र हित के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया गया। अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र कृष्णानी ने बताया कि राजा दाहिर सेन लोधी सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 में आक्रमण किया था।

सहज योग से मानसिक स्वास्थ्य के गुर सिखाए

दुर्ग। पुलिस लाइन दुर्ग के दधीचि प्रशिक्षण हॉल में सहज योग द्वारा स्वयं को पहचानो, विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और नशामुक्ति को बढ़ावा देना रहा। सहज योग विशेषज्ञ उषा अग्रवाल और उनकी टीम ने ध्यान व आत्म–जागरूकता के जरिए मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवनशैली विकसित करने के तरीके बताए। सत्र में सहज योग के सात प्रमुख चक्रों के महत्व पर चर्चा की। बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर कार्य की पहली आवश्यकता है।

फिर जिंदा हुआ महादेव ऐप का भूत; सौरभ-भूपेश का चैट वायरल, एक्स सीएम ने बताया फर्जी, 2 पर केस

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। क्रिकेट सट्टा और मनी लांडरिंग से जुड़ा महादेव ऐप का भूत एक बार फिर निकल आया है। इस ऐप से आए राजनीतिक भूचाल से कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा है। एक इंस्टाग्राम चैट वायरल हो रहा है जिसमें कथित रूप से महादेव ऐप का संचालक सौरभ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं।

महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के कथित इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कथित मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई–3 थाने पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वायरल कंटेंट को फर्जी बताते हुए नाराजगी जताई है। साथ ही भूपेश कहा कि फर्जी जानकारी वायरल करने वालों के खिलाफ मेरी लीगल टीम कानूनी कार्रवाई करेगी।

दरअसल, वायरल चैट में सीएम भूपेश बघेल के नाम से एक मैसेज दिख रहा है। इसमें कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर को कहा गया है कि नंबर भेजो अपना, बात करना चाहते हैं। इन यूट्यूबर्स ने इसे लेकर खबरें चलाई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में दावा किया गया है कि महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के कथित इंस्टाग्राम अकाउंट और भूपेश बघेल के नाम से जुड़े एक कथित यूजरनेम के बीच मैसेज में बातचीत हुई है।

इसके स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

हाईकोर्ट के आदेश पर भिलाई निगम ने की कार्रवाई, नंदिनी रोड से हटाया अवैध कब्जा

आवागमन बाधित कर कर रहा था व्यवसाय, निगम प्रशासन को करता रहा गुमराह

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जोन–4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित ग्रुप–ए भूखंड क्रमांक–2 के पूर्व दिशा में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस संबंधी पारित आदेश के पालन में की गई।

जानकारी के अनुसार उक्त स्थल पर उत्पल घोष द्वारा आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। निगम प्रशासन ने 11 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन उस दौरान कब्जाधारी द्वारा स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा गया। मांग को देखते हुए निगम ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया।

इसके बाद बुधवार 17 जून 2026 को निगम प्रशासन ने दोबारा सख्त कार्रवाई करते हुए जोन–4 राजस्व विभाग, बेदखली दल और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया।

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों एवं शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए आगे भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा तथा निगम अमले ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। निगम प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक भूमि एवं मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने तथा नियमों का पालन करने की अपील की है।

निविदा शर्तों के उल्लंघन पर निगम ने दो ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्ट

- अमानत राशि राजसात, तीन निर्माण कार्यों की निविदाएं निरस्त
- जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर दुर्ग ने निविदा शर्तों का पालन नहीं करने और कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले दो ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आगामी एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

निगम प्रशासन द्वारा मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन तथा ठेकेदार शशांक सिंह बैंस को निगम की सभी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उनकी जमा अमानत राशि राजसात करते हुए संबंधित निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है।

अधोसंरचना मद अंतर्गत साइंस कॉलेज के बाजू केनाल रोड निर्माण कार्य हेतु मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन द्वारा 10.99 प्रतिशत कम दर पर निविदा स्वीकृत कराई गई थी। किंतु ठेकेदार द्वारा न तो एफडीआर जमा किया गया और न ही अनुबंध निष्पादित करने के लिए उपस्थिति दी गई। निगम ने 2.20 लाख रुपये की अमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी तथा फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया।

इसी प्रकार ठेकेदार शशांक सिंह बैंस द्वारा वार्ड 22 में रेलवे लाइन के पास दुर्गा टेंट हाउस तक रोड निर्माण कार्य तथा वार्ड क्रमांक 60 तालाब के किनारे मेन रोड से मंच तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 25.22 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत कम दर पर निविदा प्रस्तुत की गई थी। निविदा शर्तों के उल्लंघन के चलते वार्ड 22 के कार्य में जमा 17,800 रुपये तथा वार्ड 60 के कार्य में जमा 23,500 रुपये की अमानत राशि राजसात कर ली गई है।

दल्ली मैकनाइज्ड माइंस के सिलिका रिडक्शन प्लांट ने 20 लाख टन संचयी उत्पादन का आंकड़ा पार किया

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत संचालित दल्ली मैकेनाइज्ड माइंस के सिलिका रिडक्शन प्लांट (एसआरपी) ने 04 जून 2026 को 20 लाख टन संचयी उत्पादन का महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया। यह उपलब्धि लौह अयस्क संसाधनों के अधिकतम एवं दक्ष उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उल्लेखनीय है कि सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन 23 जून 2023 को किया गया था तथा अक्टूबर 2023 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। संयंत्र ने 07 मई 2025 को संचालन प्रारंभ होने के 563 दिनों के भीतर 10 लाख टन उत्पादन का आंकड़ा प्राप्त किया था। इसके बाद अगले 10 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य मात्र 393 दिनों में हासिल किया गया, जो संयंत्र की बढ़ती उत्पादकता एवं परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

सिलिका रिडक्शन प्लांट, जिसे बेनीफिशिएशन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना उच्च सिलिका युक्त 1 एमएम से कम आकार के लौह अयस्क फाइंस के उन्नयन हेतु की गई है। यह अत्याधुनिक बेनीफिशिएशन तकनीक से सुसज्जित है, जिसके माध्यम से लौह अयस्क में उपस्थित सिलिका की मात्रा को कम कर भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाता है।

यह परियोजना सेल की उस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत निम्न श्रेणी के लौह अयस्क संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। छह दशक से अधिक पुराने दल्ली–राजहरा खदान क्षेत्र में लौह अयस्क की गुणवत्ता में क्रमिक कमी को देखते हुए 1 एमएम से कम आकार के लौह अयस्क फाइंस का बेनीफिशिएशन आवश्यक हो गया था, ताकि ब्लास्ट फर्नेस संचालन के लिए अपेक्षित गुणवत्ता का अयस्क उपलब्ध कराया जा सके।

उन्नत गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की उपलब्धता से भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेसों में हॉट मेटल उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है। साथ ही कोक की खपत में कमी, फर्नेस दक्षता में वृद्धि तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी यह संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार सिलिका रिडक्शन प्लांट सेल की सतत एवं पर्यावरण–अनुकूल इस्पात उत्पादन की प्रतिबद्धता को भी सशक्त बना रहा है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर निगम की नजर, बंद मिलने पर होगी कार्रवाई

श्रीकंचनपथ समाचार

रिसाली। आवासों और व्यावसायिक परिसर में बने वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की निगम जांच करेगा। वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद या फिर कंडम होने पर नगर पालिक निगम रिसाली प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा। इसके लिए आयुक्त मोनिका वर्मा न केवल टीम का गठन की है, बल्कि सूची के आधार पर जल संरक्षरण के लिए बनाए सोक पिट का सत्यापन भी करा रही है।

नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा ने निर्धारित माप दण्डों पर तैयार वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सत्यापन करने का निर्देश दी है। आयुक्त ने बताया कि वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद या फिर कंडम मिलने पर नियमानुसार वे कार्यवाही भी करेंगी। उन्होंने ने बताया कि वर्तमान समय में शासन लगातार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है। शासन के निर्देश पर ही पूरे क्षेत्र में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की जा रही है। भवन निर्माण के समय सशर्त दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार जल संरक्षण के लिए कदम उठाया जाना निर्धारित है। अगर किसी प्रकार की कोताही बर्ती गई तो पहले समझाइश दी जाएगी अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त मोनिका वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि घर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थल पर बने वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बारिश के पूर्व सभी संधारित कर लें।

क्यों आवश्यक है-

वर्तमान समय में भूमिगत जल स्त्रोत लगातार गिरते जा रहा है। पेयजल अथवा निस्तारी के लिए पानी की आपूर्ति करना एक चुनौति के रूप में सामने खड़ा हुआ है। यही वजह है कि आने वाले समय में पेयजल बाधित न हो इसके लिए बारिश के पानी को संरक्षित कर भूमिगत जल के स्त्रोत को बढ़ाने देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक जगहों पर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है।

भिलाई नगर निगम के आयुक्त ने दिये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

विकास में तेजी के साथ ही अवैध निर्माणों पर हो सख्ती

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन–03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन आकांक्षी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, पुल निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध निर्माण और सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफकड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

आयुक्त ने पावर हाउस छावनी थाना के सामने स्थित लाल मैदान का निरीक्षण किया और आवश्यक सुझाव दिये। इसके बाद फल मंडी क्षेत्र में पूर्व से निर्मित शौचालय की स्थिति का जायजा लेते हुए साफ–सफाई बनाए रखने, नलों में टोटी लगाने तथा पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश दिए। शौचालय परिसर के समीप नव निर्मित भवन का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जवाहर मार्केट में नागरिकों और व्यापारियों की सुविधा के लिए बनाए गए सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने कहा गया। वहीं टाटा लाइन रोड के समीप नाली पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

आयुक्त ने सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखकर यातायात बाधित करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा वार्डों में नालियों के ऊपर स्लैब डालकर किए गए अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी स्लैब हटाने और तोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नालियों पर स्लैब होने से सफाई कार्य प्रभावित होता है और जल निकासी व्यवस्था बाधित होती है। सूर्या नगर कैम्प–2 में निर्माणाधीन आधुनिक शौचालय तथा वार्ड–36 श्याम नगर स्थित महिला शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने दोनों स्थलों पर कार्यों को शीघ्र पूरा करने और नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, पार्षद प्रतिनिधि त्रिलोचन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पेट्रोल पंप के कारण खोदे गए गड्ढे से बिजली पोल के गिर जाने का खतरा

भिलाई। निगम प्रशासन ने कोहका में बन रहे अवैध पेट्रोल पंप के निर्माण पर तो रोक लगा दिया पर खोदे जा चुके गड्ढों को यूं ही छोड़ दिया है। यह गड्ढा बिजली पोल से सटा हुआ है। जमीन हटने के कारण यह खंभा कभी भी गिर सकता है। इस सड़क से स्कूली बच्चों का आना जाना होता है जिसमें स्कूल बस भी शामिल है। इसकी शिकायत भी निगम कमिश्नर से की जा चुकी है पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जनता भयभीत और आशंकित है। भाजपा प्रदेश संवाद प्रमुख झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक शारदा गुप्ता, आनंद बसंत भारती, प्रशांत पासवान, सुगंधी वर्मा ने बिजली पोल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी किसानों की भरोसेमंद साथी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे शासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। इसका सकारात्मक उदाहरण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड निवासी किसान राम बलारिक यादव हैं। खरीफसीजन की तैयारियों के दौरान उन्हें समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण बोआई प्रभावित होने की चिंता सताने लगी थी। खेती-किसानी पर निर्भर किसान के लिए यह स्थिति काफी परेशानी भरी थी। समस्या के समाधान के लिए राम बलारिक यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही कृषि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की। विभागीय अधिकारियों के प्रयासों से किसान को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराया गया, जिससे वे समय पर अपनी खेती की तैयारियां पूरी कर सके और बोआई कार्य प्रभावित होने से बच गया। श्री राम बलारिक यादव ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या का इतनी शीघ्रता से समाधान हो जाएगा।

पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ - कलेक्टर

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक लेकर विभिन्न विभागों एवं बैंकों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के तहत प्रदत्त लक्ष्यों की प्रगति, लंबित प्रकरणों एवं विभागीय समन्वय की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर वर्मा ने सभी बैंक अधिकारियों से टारगेट के अनुसार योजनाओं के प्रकरणों में तेजी लाने और पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बैठक में जिले के सभी बैंकों के अधिकारियों को शासन की योजनाओं के तहत आने वाले ऋण आवेदनों पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से हितग्राहियों को सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए बैंक में ऋण आवेदन भेजे जाते हैं, ऐसे में इन आवेदनों को किसी भी स्तर पर लंबित न रखा जाए।

भविष्य पीढ़ियों के लिए खेत बचाना जरूरीः सकनी

बीजापुर। इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञानं केंद्र, बीजापुर द्वारा इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालया के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल व निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस. एस. टुटेजा के निर्देशानुसार व कृषि विज्ञान केंद्र, बीजापुर के वरिष्ठ बैज्ञानिक एवं प्रमुख अरुण सकनी के मार्गदर्शन में दिनांक 17 जुन 2026 को खेत बचाओ अभियान अंतर्गत ब्लॉक भैरमगढ़ ग्राम दरकपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया । श्री सकनी ने भविष्य के पीढ़ियों के लिए खेत बचाने पे जोर दिया, उसके लिए जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, हरी खाद अपनाने पे जोर दिया।

मुख्यमंत्री साय ने दी 603 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में जिलेवासियों को 603 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये की लागत वाले 76 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री साय ने 86 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए 46 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 516 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये की लागत से प्रारंभ होने वाले 30 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी तथा विकास को नई गति प्राप्त होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों एवं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सुशासन के माध्यम से योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 757 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों में राहत दी जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुक्त योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली खर्च से राहत मिलने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को ऋण, खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए नैनो यूरिया के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत कम होती है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है। उन्होंने नागरिकों से इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर नई पहचान स्थापित कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की रोशनी पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार है। उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिले में आज जिन विकास कार्यों की शुरुआत हुई है, उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, विद्युत तथा जनसुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा और जिले के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरियाबंद जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और धार्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाला राजिम, राजीव लोचन मंदिर तथा कुलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। राज्य सरकार द्वारा इन धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान सुपेबेड़ा क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेल नदी पर 7 करोड़ रुपये की लागत से एनीकट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है तथा 16 जून से 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करें जो अभी तक विद्यालय से बाहर हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गठन के तत्काल बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में प्रदेश में 26 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 19 लाख 70 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

पीएम सेतु के तहत आईटीआई होंगी अपग्रेड

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पीएम-सेतु (PM-SETU) योजना के तहत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आधुनिक और उद्योग-अनुकूल बनाया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षित कर रोजगार के काबिल बनाना है। पुरानी मशीनों को बदलकर नई तकनीक वाली मशीनें लगाई जाएंगी और डिजिटल कंटेंट व स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य में पीएम सेतु योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने योजना के तहत राज्य की चयनित औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की जा रही कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में पीएम सेतु के तहत राज्य के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की सलाह से स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आईटीआई अपग्रेड करने और उद्योग नेतृत्व वाले एंकर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के चयन हेतु जारी किए जाने वाले पात्रता मापदण्डों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। इसी तरह से ईओआई में भाग लेने वाले उद्योगों सहित समस्त पात्र उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध के बारे में प्रक्रिया में सहभागिता हेतु अवसर प्रदान करने पर भी चर्चा हुई।

इसी तरह से प्रधानमंत्री सेतु योजना अंतर्गत एंकर इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के ऑनबोर्डिंग हेतु जारी किए जाने वाले ड्राफ्ट के प्रस्ताव के अनुरोध के बारे में भी चर्चा हुई। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. सहित वित्त विभाग, श्रम, स्कूल शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल, रोजगार एवं प्रशिक्षण, सीआईआई एवं भारत सरकार कौशल विकास और उद्यम शीलता महानिदेशालय छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों ने भाग लिया।

स्वास्थ्य सुरक्षा में बड़ी छलांगः आयुष्मान भारत योजना में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का शानदार प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में एक मिसाल पेश की है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते जिले ने राज्य स्तरीय रैंकिंग में महज एक महीने के भीतर 19वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंचकर 7 पायदान की शानदार छलांग लगाई है। इस बेहतरीन सुधार के साथ ही जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड पंजीयन पूरा कर लिया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा का मिलेगा मजबूत कवच

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। जिले में पंजीयन का ग्राफ94 प्रतिशत तक पहुंचने का सीधा मतलब यह है कि अब जिले के एक बहुत बड़े वर्ग को बीमारी के समय इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्ति मिलेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल सकेगा।

यह सफलता प्रशासनिक सूझबूझ और जमीनी स्तर पर की गई कड़ी मेहनत का नतीजा है। कलेक्टर के कुशल नेतृत्व और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सतत मार्गदर्शन में जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन अभियान को एक मिशन की तरह चलाया गया। रैंकिंग में इस ऐतिहासिक सुधार के लिए जिले के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों का मौके पर ही पंजीयन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर लोगों को योजना के फायदों के प्रति जागरूक किया, जिससे लोग खुद कार्ड बनवाने आगे आए।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में जो गति पकड़ी है, वह बेहद प्रभावशाली है। मात्र एक माह के अल्प अंतराल में जिले ने अपनी कार्यकुशलता का प्रमाण देते हुए राज्य स्तरीय रैंकिंग में 19 वें स्थान से छलांग लगाकर 12वां स्थान हासिल कर लिया है।

यह 7 पायदान का सुधार प्रशासनिक सक्रियता का ही परिणाम है। इस तीव्र प्रगति के साथ ही, जिला अब अपने निर्धारित पंजीयन लक्ष्य के 94 प्रतिशत के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर चुका है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले ने भले ही 94 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन प्रशासन अब बचे हुए 6 प्रतिशत हिस्से को भी जल्द से जल्द कवर करना चाहता है।

पीएम स्वनिधि योजना से पथ विक्रेताओं और लघु व्यवसायियों का बढ़ रहा आत्मविश्वास

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में छोटे व्यापारियों एवं पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी एवं फुटकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

प्रदेशभर में संचालित विशेष शिविरों और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का कार्य लगातार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे छोटे व्यवसायियों को आवश्यक कार्यशील पूंजी प्राप्त हो रही है और उनके कारोबार को नई गति मिल रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम जतरो निवासी

उमाचंद सिंह इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं।

फल विक्रय का कार्य करने वाले उमाचंद सिंह को व्यवसाय विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्हें पहले 10 हजार रुपये की ऋण सहायता मिली थी, जिसका समय पर उपयोग और पुनर्भुगतान करने के बाद उन्हें 25 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ।

सरगुजा से वैश्विक बाजार तकः संत गहिरा गुरु विवि और अर्थीफैक्ट्ज के बीच MoU, युवाओं को मिलेंगे स्वरोजगार के नए अवसर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय और भोपाल की प्रतिष्ठित संस्था 'अर्थीफैक्ट्ज आर्टिज़ंज प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल ' के बीच एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुआ है। इस रणनीतिक साझेदारी से न केवल सरगुजा संभाग, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं और स्थानीय शिल्पकारों के लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे।

इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ स्थानीय हस्तशिल्पियों, कुम्हारों और पारंपरिक कृषि उत्पादकों को आधुनिक तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने, उनकी ब्रांडिंग करने और ऑनलाइन बेचने के व्यावहारिक गुर सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कंपनी रजिस्ट्रेशन, डिजिटल कैटलॉगिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आधुनिक मॉड्यूल्स से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण को सुगम बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री पूरी तरह नि:शुल्क दी जाएगी।

पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, यह स्त्थ तृतीयक क्षेत्रों में भी युवाओं का भविष्य संवारेगा। छात्र-छात्राओं को लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सेवा, व्यापार और कॉर्पोरेट व्यवसाय के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार रोजगार हासिल कर सकें।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले की पहल पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी तथा अर्थीफैक्ट्ज आर्टिजंज की डायरेक्टर सुश्री अपर्णा अवस्थी ने इस समझौते पर मुहर लगाई। यह पहल स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने, युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और उन्हें पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

जैविक खेती से गांव होंगे समृद्ध, किसान बनेंगे आत्मनिर्भर : अरुण साव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में कृषि विभाग की एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा) योजना अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यशाला में कहा कि जैविक खेती से गांव समृद्ध होंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप, सभापति अंबालिका साहू, अनुसुईया जागेंद्र कश्यप, रतनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष लवकुश कश्यप, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल, डॉ आर.के.एस. तोमर, श्री राजेश सिंह, श्री राकेश तिवारी, श्री धीरेंद्र दुबे और श्री दिनेश कौशिक सहित कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि किसान धरती पुत्र हैं। कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि गांवों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैविक खेती समय की आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और गौसंवर्धन को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांवों में आपसी सहयोग और सामुदायिक सहभागिता से ही आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों का किया गया सम्मान

कार्यशाला के दौरान जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान जदूनंदन साहू, हजारीलाल पटेल, श्रद्धा मिश्रा एवं शिल्पी राजपूत सहित अन्य किसानों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ बृजलाल राठौर ने जैविक खेती की तकनीकों, लाभों एवं संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन लागत कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद प्राप्त करने के उपाय बताए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है जिनसे किसानों को आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि गांवों को फिर से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति गांव, किसान और जनभागीदारी में निहित है। किसानों का परिश्रम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती के साथ-साथ विविध एवं रसायनमुक्त खेती को अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण तथा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही समृद्ध भविष्य की आधारशिला है। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉ. गीत शर्मा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ना है।

'मेरा जहरी बलमा, बैरी बलमा'; सपना चौधरी ने शेयर की रील; नेटिजंस बोले- 'हम दुआ करते हैं आपकी जोड़ी सलामत रहे'

हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के चलते सुर्खियों में हैं। पति वीर साहू के साथ उनका घरेलू विवाद चल रहा है। सपना ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें सपना चौधरी अपने ही गाने पर धमाकेदार अंदाज में परफॉर्म करती दिखी हैं।

निजी जिंदगी से अलग सपना चौधरी इन दिनों अपने एक गाने को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। 'जहरी बलमा' टाइटल वाला यह सॉन्ग हाल ही में रिलीज हुआ। सपना ने आज गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने इसी गाने पर डांस करती दिख रही हैं। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'मेरा जहरी बलमा, मेरा बैरी बलमा'।

पति से विवाद के बीच सपना का क्रिप्टिक पोस्ट

पति से विवाद और कानूनी एक्शन के बीच सपना चौधरी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं और लगातार पोस्ट शेयर कर रही हैं। अब वे अपने इस डांस वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया था। इसमें लिखा था, 'दो पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए। वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी'।

नेटिजंस बोले- 'जोड़ी सलामत रहे'

सपना चौधरी के हालिया डांस वीडियो पर नेटिजंस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फैंस दुआ कर रहे हैं कि हरियाणवी क्वीन की शादीशुदा जिंदगी में जल्द सब ठीक हो जाए। एक यूजर ने लिखा, 'हमारी प्रार्थना है कि आपकी जोड़ी सलामत रहे'। एक यूजर ने लिखा, 'ऐसे गाने सुनकर वीर साहू भी बेहद खुश होते होंगे'। वहीं, कुछ यूजर्स सपना के डांस और खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। सपना की पर्सनल लाइफकी बात करें तो उन्होंने साल 2020 में वीर साहू से शादी की थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सपना और वीर के दो बेटे- पोरस और शाहवीर हैं।

चेहरे के दाग-धब्बों के साथ ही झुर्रियां भी दूर करेगी फिटकरी, ऐसे करें इस्तेमाल

फिटकरी के बहुत सारे फायदे हैं। शरीर से बह रहे खून को ये बंद करने के काम आता है। इसीलिए मर्दों की शेविंग किट में फिटकरी जरूर होती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल त्वचा पर करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फिटकरी को दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करने से ना केवल दाग-धब्बे और झुर्रियां दूर होती हैं। बल्कि आंखों के नीचे के काले घेरे और सूजन भी कम करने में मदद करता है। तो चलिए जानें फिटकरी को किस तरह से इस्तेमाल करने से फायदा पहुंचता है त्वचा को।

डार्क स्पॉट और सूजी आंखों को करता है कम

आंखों के नीचे सूजन आ गई है या फिर काले घेरे रहते हैं तो फिटकरी और गुलाबजल के मिश्रण से फायदा पहुंचता है। सबसे खास बात कि फिटकरी स्किन पर किसी तरह का इरिटेशन भी नहीं करती है। फिटकरी के पाउडर में गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर दस मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गर्म पानी से चेहरा धो लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा।

त्वचा में लाए कसाव

चेहरे की त्वचा पर ढीलापन दिखने लगा है तो फिटकरी से बने टोनर को चेहरे पर लगाएं। ये काफी असरदार होता है। टोनर बनाने के लिए सबसे पहले फिटकरी को पानी में डालें। साथ में कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल लें। पानी को उबाल लें। उबालने से फिटकरी तुरंत पानी में घुल जाएगी। इसके बाद गैस बंद कर पानी को छान लें। फिर इसमे कुछ बूंद ग्लिसरीन की मिलाकर किसी शीशी में रख लें। इसे टोनर के तौर पर चेहरे पर इस्तेमाल करें।

कील मुंहासे के निशान हो जाएंगे गायब

चेहरे पर अगर कील -मुंहासे के दाग रह गए हैं तो फिटकरी को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाए। इस पैक को बनाने के लिए फिटकरी के पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर पेस्ट बना लें। पेस्ट के लिए दूध का इस्तेमाल करें। 15 मिनट बाद चेहरे को गर्म पानी से धो लें। इससे चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने में मदद मिलेगी।

अपनी जरूरत के अनुसार करें प्रयोग

त्वचा की जरूरत के हिसाब से इनमे से किसी भी तरीके से फिटकरी का प्रयोग करें। दाग-धब्बे दूर करने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय से मिलीं सामंथा कहा- हमेशा से पता था वो कुछ बड़ा करने वाले हैं

सामंथा रुथप्रभू ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय से चेन्नई में मुलाकात की है। इस स्पेशल मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट कर सामंथा ने विजय की तारीफों के पुल बांधे हैं।

सामंथा ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें पोस्ट कर लिखा है, 'जब मैं आज चेन्नई पहुंची, तो मुझे बेहद खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि विजय सर सिर्फ पर्दे पर हीरो बनने के लिए नहीं बने हैं। उनकी एनर्जी, उनकी मौजूदगी और लोगों का उनके प्रति प्यार हमेशा यह एहसास दिलाता था कि उनका मकसद इससे भी बड़ा है।'

आगे उन्होंने लिखा, 'मुझे सबसे ज्यादा जिस बात से प्रेरणा मिलती है, वह है एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस। ऐसी जगह जाना, जहां दांव कहीं ज्यादा बड़े हों, जबकि आप पहले ही अपने पुराने क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हों। यह फैसला इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि वह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आप बदलाव ला सकते हैं।'

'मेरा मानना है कि जिंदगी में कभी न कभी हम सभी के सामने ऐसा मौका आता है, जब हमें खुद से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है और यह सवाल पूछना पड़ता है कि हम समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उस पुकार का जवाब देते हैं।'

आखिर में सामंथा ने लिखा, 'मुझे लगता है कि विजय सर उन लोगों को भी हैरान कर देंगे, जो पहले से ही उन पर भरोसा करते हैं। इसकी वजह उनका पद नहीं, बल्कि वह नीयत है जिसके साथ वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं उनके लिए शक्ति, समझदारी और अपने रास्ते पर डटे रहने का साहस की कामना करती हूं। और हर युवा के लिए यह एक याद दिलाने वाली बात है कि जिंदगी उस सपने से कहीं बड़ी हो सकती है, जिससे आपने शुरुआत की थी।'

इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखी विजय-सामंथा की जोड़ी-

कथी (2014): एआर मुरुगाडोस द्वारा निर्देशित इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में विजय ने डबल रोल निभाया और सामंथा उनकी लीड एक्ट्रेस थीं।

थेरी (2016): एटली द्वारा निर्देशित यह एक बड़ी एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

मार्सल (2017): यह एक सुपरहिट ड्रामा फिल्म थी जिसमें इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

अदा शर्मा ने मराठी सिनेमा की तरफ बढ़ाए कदम, डेब्यू फिल्म 'गजरा' का एलान

'द केरल स्टोरी' और '1920' जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाली अदा शर्मा अब मराठी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। उनकी पहली फिल्म होगी 'गजरा'। इसका एलान हो गया है। साथ ही पहली झलक भी सामने आई है।

अदा शर्मा की डेब्यू मराठी फिल्म 'गजरा' का आधिकारिक एलान कर दिया गया है। यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी। अदा इसमें लीड रोल निभाती नजर आएंगी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर कर यह जानकारी साझा की है। साथ ही लिखा है, 'मराठी में मेरी पहली फिल्म 'गजरा'। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है'।

अदा शर्मा ने आगे लिखा है, 'मेरी पहली फिल्म '1920' से 'केरल स्टोरी', 'सनफ्लावर', 'कमांडो', 'बस्तर', 'रीता सान्याल' तक, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। हार्टअटैक, क्षणम, राणा विक्रम और मेरी सभी साउथ फिल्मों के लिए भी खूब प्यार दिया। मुझे अपने मराठी डेब्यू के लिए भी आप सभी के आशीर्वाद, साथ और प्यार की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी को गौरवान्वित कर सकूंगी और एक ऐसी फिल्म बना सकूंगी, जिसे आप सभी पसंद करें।

सच्ची घटना पर आधारित होगी कहानी?

फिल्म का पोस्टर काफी दिलचस्प है। इससे सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक अंधेरे, परेशान करने वाली और कठिन कहानी का संकेत मिल रहा है। अदा शर्मा की इस फिल्म का निर्देशन श्रेयस जाधव कर रहे हैं। वहीं, फिल्म का निर्माण अमोल बोरकर कर रहे हैं। गणराज स्टूडियोज की पेशकश फिल्म 'गजरा' जिग जैग प्रोडक्शन्स की पहली फिल्म है। अदा ने अपने पोस्ट में यह बताया है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है।

क्या ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं योगासन ?

मधुमेह, मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी से संबंधित विकार है, इसमें रक्त शर्करा का स्तर काफी तेजी से बढ़ने लगता है जिसके कारण शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। ब्लड शुगर का कम या अधिक होना दोनों ही गंभीर स्थिति है, ऐसे में सभी लोगों को इसे नियंत्रित रखने के उपाय करते रहने की सलाह दी जाती है। पर सिर्फ आहार संबंधी सुधार को विशेषज्ञ ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं, इसके लिए शारीरिक सक्रियता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शोध बताते हैं कि जो लोग अक्सर बैठे रहने वाले काम करते रहते हैं उनमें अन्य लोगों की तुलना में मधुमेह का जोखिम अधिक होता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक योगासनों को मधुमेह के उपचार और रोकथाम के लिए सबसे आशाजनक और किफायती विकल्प माना जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि योग और व्यायाम की आदत हाइपरग्लेसेमिया यानी कि रक्त शर्करा बढ़ने की स्थिति को कम कर सकते हैं। ब्लड शुगर को नियंत्रित कर इससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में भी योगासनों की आदत काफी लाभकारी मानी जाती है। आइए जानते हैं डायबिटीज रोगियों के लिए कौन से अभ्यास फायदेमंद हो सकते हैं?

धनुरासन योग का करिए अभ्यास

धनुरासन योग मुद्रा अग्न्याशय को मजबूत करने में मदद करती है, इसलिए इसे मधुमेह वाले रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने, पाचन को बढ़ावा देने और शारीरिक निष्क्रियता को दुष्प्रभावों को कम करने के लिए भी कारगर अभ्यास है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उन्हें दिनचर्या में इस योगाभ्यास को जरूर शामिल करना चाहिए।

बालासन योग का अभ्यास

बालासन या चाइल्ड पोज योग आपके हैमस्ट्रिंग, रोटेटर मांसपेशियां और स्पाइनल एक्सटेंसर का अभ्यास करने में सहायक है। ऐसे में यह तनाव, थकान और पीठ और गर्दन के दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। बालासन योग को विशेषज्ञ डायबिटीज की समस्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर योगासनों में से एक मानते हैं। यह योगाभ्यास इंसुलिन-उत्पादक बीटा कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करता है।

भुजंगासन योग

भुजंगासन योग, शरीर को आराम देने के साथ दिमाग को भी शांत करने वाला अभ्यास है। यह आपके मस्तिष्क के तनाव को कम करने के साथ शरीर के अंगों में रक्त संचार बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है।

शरीर के लिए क्यों आवश्यक है फाइबर युक्त चीजों का सेवन?

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अक्सर आपने पौष्टिक चीजों के सेवन की आवश्यकताओं के बारे में सुना होगा। पर क्या जिस तरह का भोजन हम रोजाना कर रहे हैं, उसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि भोजन में पौष्टिकता की कमी के कारण कई तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पेट की समस्याओं के रूप में देखने को मिल रहा है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि आमतौर पर लोगों की फास्ट और जंक फूड्स की तरफ रुचि अधिक देखी जा रही है, इसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल कम जबकि फैट की अधिकता होती है, ऐसे में इनका अधिक सेवन आपको बीमार कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पेट की बीमारियों से बचे रहने के लिए सभी लोगों को आहार में फाइबर युक्त चीजों के अधिक सेवन पर ध्यान देना चाहिए। डायट्री फाइबर आपके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ वजन को नियंत्रित रखने में सहायक माने जाते हैं। फाइबर युक्त चीजों का सेवन करने से कब्ज होने की दिक्कत कम होती है और यह आंतों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके लिए कच्चे फल-सब्जियों, साबुत अनाज, चिया सीड्स आदि का सेवन अधिक करें। आइए आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं।

वजन कम करने की कोशिश में लगे लोगों के लिए फायदेमंद

फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ न केवल आपके पाचन को ठीक रखने में मदद करते हैं, साथ ही यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रखते हैं। इससे आपको अतिरिक्त खाने की इच्छा नहीं होती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने नियमित रूप से फाइबर वाली चीजों का सेवन किया, उनमें वजन बढ़ने का खतरा काफी कम पाया गया। मोटापा के खतरे से बचे रहने के लिए भी फाइबर वाले आहार आपके लिए लाभकारी हैं।

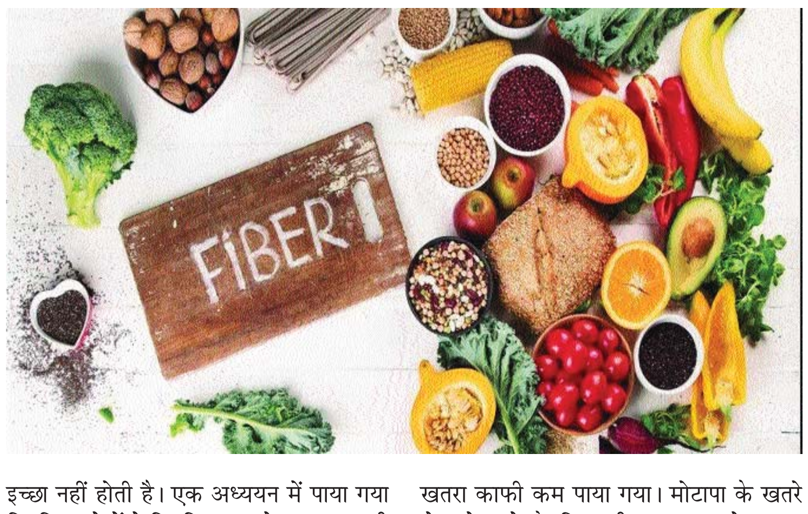

आंत रहता है स्वस्थ

अच्छे पाचन के लिए आंतों का स्वस्थ बना रहना आवश्यक माना जाता है। फाइबर वाली चीजों के सेवन की आदत बनाकर आप आंतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हाई फाइबर डाइट आपके बृहदान्त्र को स्वस्थ रखकर बवासीर और मांस के उभार जैसी समस्याओं के जोखिम को कम कर देते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि फाइबर युक्त आहार कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने में भी सहायक है।

मधुमेह रोगियों को आहार में जरूर करना चाहिए शामिल

रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी फाइबर युक्त चीजों के सेवन को बढ़ाना लाभदायक माना जाता है। शोध से पता चलता है कि मधुमेह वाले लोगों में फाइबर, विशेषरूप से घुलनशील फाइबर, शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता है जिससे डायबिटीज बढ़ने का जोखिम कम रहता है। रक्त शर्करा के स्तर को बेहतर बनाए रखने और विशेषकर टाइप-2 डायबिटीज के विकास के जोखिम कम करने में इसके लाभ पाए गए हैं।

लंबी आयु के लिए करें सेवन

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आप भी लंबी आयु चाहते हैं तो इसमें आहार की विशेष भूमिका हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि आहार में फाइबर वाली चीजों की वृद्धि करके कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और कई तरह के कैंसर के विकसित होने और इसके कारण होने वाली मौत के खतरे को कम किया जा सकता है। ऐसे में आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाकर आप लंबी आयु भी पा सकते हैं।

चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना से छत्तीसगढ़ के विकास और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी नई शक्ति : मुख्यमंत्री साय

755 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति जताया आभार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय रेल द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 755 करोड़ रूपए की लागत से चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में रेल अधोसंरचना का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने पर यात्री सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु होगी, परिचालन संबंधी बाधाएं कम होंगी तथा भविष्य में अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरबा देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में महत्वपूर्ण पहचान रखता है और यहां से देश के विभिन्न हिस्सों तक कोयले की आपूर्ति होती है। चांपा-कोरबा रेल खंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की खदानों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस परियोजना के पूर्ण होने से कोयला परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक आधार और अधिक मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में तीसरी रेल लाइन का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया दूरदर्शी निर्णय है। इससे अतिरिक्त माल परिवहन को सुगम बनाया जा सकेगा और रेल परिचालन अधिक दक्ष एवं प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह परियोजना केवल कोयला परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिलेगा। बेहतर रेल संपर्क से उद्योगों को मजबूती मिलेगी, निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे कोरबा, जांजगीर-चांपा सहित आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि चांपा-कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान करेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क, सुदृढ़ लॉजिस्टिक व्यवस्था और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश के विकास में और अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ को रेल अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्राथमिकता मिली है। प्रदेश के रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, तीसरी-चौथी लाइन और आधुनिक रेलवे स्टेशनों के विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी को लगातार सशक्त किया जा रहा है। हाल ही में धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाना भी इसी विकास दृष्टि का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में स्वीकृति मिलना जशपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष स्नेह और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लंबे समय से रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे जशपुरांचल को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की नई आधारशिला है। इससे पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा वनांचल क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा।

खास खबर

दिव्यांग बच्चों के शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड निर्माण के निर्देश

कोरबा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने जिले के प्री-प्राइमरी, एलिमेंट्री एवं सेकेंडरी विद्यालयों में नामांकित दिव्यांग बच्चों के यूडीआईडी कार्ड का शत-प्रतिशत निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र दिव्यांग बच्चों की जानकारी संकलित कर उनका यूडीआईडी कार्ड समयबद्ध रूप से बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं समग्र शिक्षा विभाग को आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है। यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजनों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पहचान है, जिसके माध्यम से उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं, सेवाओं एवं अधिकारों का लाभ प्राप्त होता है। जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जिले का कोई भी पात्र दिव्यांग बच्चा यूडीआईडी कार्ड से वंचित न रहे।

तीन दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर होगा आयोजन

कोण्डागांव। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में ''विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के'' कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय पंजीकरण शिविर का आयोजन प्रत्येक राजस्व अनुभाग स्तर पर किया जाएगा। इस अवसर पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के कोण्डागांव, फरसगांव और केशकाल अनुभाग अंतर्गत 3 दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविरों का आयोजन 18 जून 2026 से 20 जून 2026 तक सुनिश्चित किया गया है, इन शिविरों में मुख्य रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लिए नए पंजीकरण, त्रुटि सुधार और समस्याओं का त्वरित निवारण संबंधी कार्य किया जाएगा।

राज्य सरकार की बेहतर व्यवस्था से किसानों को समय पर मिल रहे कृषि आदान सामग्री

कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसका लाभ जिले के किसानों को सहजता से मिल रहा है, जिससे उनमें उत्साह और संतोष का वातावरण है। कोरबा जिले के देलवाड़ीह की कृषक श्रीमती शीला टोप्पो भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्हें समय पर कृषि आदान सामग्री उपलब्ध होने से खेती की तैयारियों में बड़ी सुविधा मिली है। लगभग तीन एकड़ भूमि में धान की खेती करने वाली टोप्पो इन दिनों खरीफ फसल की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उनकी कृषि भूमि भालुसटका क्षेत्र में स्थित है और वे स्वयं खेती का पूरा कार्य संभालती हैं।

डिजिटल क्रांति से संवरती बुजुर्गों की राह

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। डिजिटल क्रांति बुजुर्गों के जीवन को आसान और आत्मनिर्भर बना रही है। ऑनलाइन पेंशन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, और व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाओं से उन्हें कतारों में लगने से मुक्ति मिली है। ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के हकदारों तक पहुँचाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन जब तकनीक, संवेदनशीलता और ज़मीनी स्तर पर जागरूकता का मिलन होता है, तो सुदूर जंगलों और गाँवों में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जाती है। कुछ ऐसी ही उम्मीद और बदलाव की बयार बही नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के ग्राम पंचायत गारपा के आश्रित ग्राम मसपुर में।

मसपुर में हाल ही में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष शिविर सिर्फ सरकारी या कागजी कार्रवाई का जरिया नहीं, बल्कि कई बुजुर्गों और आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बना। यहाँ ग्रामीणों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की ताक़त से रूबरू कराया गया। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में यह चिंता बनी रहती है कि पेंशन कब आएगी और कैसे मिलेगी? इस शिविर ने इसी अनिश्चितता को दूर किया। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने खुद ग्रामीणों के बीच पहुँचकर बेहद सरल भाषा में समझाया कि कैसे उनका आधार कार्ड और बैंक खाता मिलकर उनकी पेंशन को सुरक्षित बनाता है।

शिविर में बताया गया कि बुजुर्गों को पेंशन के लिए हर साल बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। शिविर के दौरान 15 पेंशन हितग्राहियों को जब यह पता चला कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक की उनकी रुकी हुई या प्रतीक्षित पेंशन राशि सीधे उनके खातों में जमा हो चुकी है, तो उनके चेहरों की संतुष्टि देखने लायक थी। बिचौलियों के चक्कर काटे बिना, सीधे बैंक खाते में आई इस राशि ने ग्रामीणों को व्यवस्था पर एक नया भरोसा दिया है।

नए चेहरों को मिली नई उम्मीद

यह शिविर केवल पुरानी समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भविष्य की राह भी आसान की। शिविर के दौरान 2 नए पात्र हितग्राहियों के पेंशन आवेदन भी प्राप्त किए गए। प्रशासन की इस त्वरित पहल से अब इन नए आवेदकों को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और नियमानुसार जल्द ही उनके खातों में भी पेंशन की राशि पहुँचने लगेगी। प्रशासन की इस मुहिम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने ग्रामीणों से एक बेहद महत्वपूर्ण अपील की है। विभाग ने आग्रह किया है कि सभी हितग्राही अपने आधार और बैंक खाते की जानकारियों को हमेशा अद्यतन रखें। बाधा के ठीक समय पर सीधे उनके हाथों (खातों) में पहुँचती रहे।

राज्य पोषित योजना से मछुआरों को मिला मछली जाल

श्रीकंचनपथ समाचार

गरियाबंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने तथा मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में मत्स्य पालन विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत गरियाबंद जिले के ग्राम चिखली के हितग्राही लीलांबर निषाद एवं पुखराज निषाद को मछली पकड़ने हेतु मछली जाल प्रदान किया गया।

हितग्राहियों ने बताया कि वे मछली पालन के साथ-साथ मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इसके लिए वे अपने गांव के समीप स्थित सेम्हरधाप, जशपुर, नवाडीह पेंड्रा तथा गरियाबंद क्षेत्र के विभिन्न तालाबों में 10 से 12 लोगों की टीम के साथ संगठित रूप से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में मछली पकड़ने के लिए जाल किराए पर लेना पड़ता था, जिसके लिए प्रतिदिन प्रति जाल 200 से 300 रुपये तक का व्यय करना पड़ता था। मछली पकड़ने के कार्य से उन्हें औसतन 500 रुपये प्रतिदिन की आय प्राप्त होती थी। अब विभाग द्वारा स्वयं का मछली जाल उपलब्ध कराए जाने से किराए का अतिरिक्त खर्च बचेगा, जिससे उनकी शुद्ध आय में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि स्वयं का जाल मिलने से कार्य करने में सुविधा बढ़ेगी, उत्पादन और आय में वृद्धि होगी तथा परिवार की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा।

किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है - मंत्री लखनलाल देवांगन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन रायपुर में डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय (बिलासपुर) एवं आइसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए

इस अवसर पर देवांगन ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन चुनौती है उन्हें आज के दौर के अनुसार हुनरमंद बनाना। श्री देवांगन ने कहा कि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां परिवर्तन ही एक मात्र स्थिर चीज है और इस दौर में भारत को एक महा शक्ति बनाने का सबसे बड़ा सारथी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.)।

विकसित भारत के लिए ए.आई. संचालित कौशल विकास वित्तीय समावेशन और सामाजिक उद्यम विषय पर आईसेक्ट द्वारा इसका आयोजन किया गया। केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जब हम साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं तो ए.आई. केवल एक तकनीक नहीं बल्कि वह इंजन है जो हमारे कौशल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को नई दिशा और रफ्तार देगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक विकास की रोशनी देश के आखरी कोने में बैठे व्यक्ति तक न पहुंचे। वित्तीय समावेशन का मतलब है, हर नागरिक को बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था से जोड़ना। श्री देवांगन ने कहा कि आजकल सामाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार के समस्त योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। यह केवल तकनीकि उत्थान एवं ए.आई. के माध्यम से संभव हो सका है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने 5 युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. पी.के. घोष, आईसेक्ट के चेयरमेन डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पदम अजय मंडावी, डॉ. तोपलाल वर्मा,डॉ. अनुराग होता, सेंट्रल बैंक ऑफइंडिया के महाप्रबंधक राजेश भुतड़ा, भारतीय स्टेट बैंक के ललित कुमार, सीआईआई के छत्तीसगढ़ प्रमुख पदम गोयल, अनुराग गुप्ता, बजरंग गोयल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी की गई निविदाएं

शासन द्वारा रिडेवलपमेंट योजना अंतर्गत कुल पांच परियोजनाओं का टेंडर जारी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल राज्य के विभिन्न शहरों में पाँच प्रमुख रिडेवलपमेंट परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। यह पहल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहरी विकास, शासकीय परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग तथा आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं का विकास राज्य की रिडेवलपमेंट नीति के तहत किया जाएगा।

इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए मंडल द्वारा प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए गए हैं। साथ ही निजी डेवलपर्स के चयन हेतु पारदर्शी निविदा प्रक्रिया तथा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके पश्चात 27 मई 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पाँचों परियोजनाओं के अंतिम स्वरूप पर विस्तृत चर्चा कर उन्हें अनुमोदित किया गया।

प्रस्तावित परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 19.14 एकड़ है तथा वर्ष 2025-26 की संशोधित गाइडलाइन दरों के अनुसार इनका अनुमानित मूल्य लगभग 250.30 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं बी.टी.आई. रोड शंकर नगर (रायपुर), क्लब पारा (महासमुंद), कैलाश नगर (राजनांदगांव), कटघोरा (कोरबा) तथा चांदनी चौक फेज-2 (जगदलपुर) में विकसित की जाएंगी। इन पाँचों रिडेवलपमेंट योजनाओं का टेंडर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में प्रस्तावित परियोजना विशेष महत्व रखती है। यह परियोजना शहर के प्रमुख एवं विकसित क्षेत्र शंकर नगर स्थित बी.टी.आई. ग्राउंड के सामने, सिंधु भवन के समीप स्थित है। यह क्षेत्र शैक्षणिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा आवासीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। परियोजना के विकसित होने से क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार होगा तथा शासकीय परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रिडेवलपमेंट मॉडल के तहत जर्जर एवं अनुपयोगी शासकीय परिसंपत्तियों के स्थान पर आधुनिक एवं सुव्यवस्थित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार की आवश्यकता नहीं होगी। शासकीय भूमि के मूल्य का उपयोग ही परियोजनाओं के वित्तीय संसाधन के रूप में किया जाएगा। इससे शासकीय भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ राज्य को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। यह पहल निजी डेवलपर्स के लिए भी आकर्षक अवसर प्रदान करती है। उन्हें शहरों के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित प्राइम लोकेशन वाली भूमि पर परियोजनाएं विकसित करने का अवसर मिलेगा। स्पष्ट नीति, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया तथा सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी से परियोजनाओं में विश्वास और स्थिरता सुनिश्चित होगी। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिडेवलपमेंट नीति के माध्यम से अनुपयोगी एवं जर्जर शासकीय परिसंपत्तियों को आधुनिक तथा उपयोगी अधोसंरचना में परिवर्तित किया जाएगा।

कविता ध्रुव को मिली 20 हजार रुपये की सहायता राशि

गरियाबंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत गरियाबंद जिले की हितग्राही कविता ध्रुव को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। कविता ध्रुव ने बताया कि प्राप्त सहायता राशि का उपयोग वे अपने बच्चों के लालन-पालन, देखभाल एवं आवश्यक जरूरतों की पूर्ति में करेंगी। उन्होंने इस सहायता के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है।

खास खबर

सूरजपुर में तेज रफ्तार बोलेरो पलटी: डिवाइडर से टकराने से एक व्यक्ति गंभीर घायल

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंद्रपुर में गुरुवार तड़के एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो अन्य को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार, बोलेरो अंबिकापुर से बैकुंठपुर की ओर जा रही थी। चंद्रपुर के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के समय वाहन में कुल तीन लोग सवार थे। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। शुरुआती जांच में हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर दी जान, मोबाइल जब्त कर जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग। जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। भिलाई-3 थाना क्षेत्र के उमदा गांव में 17 वर्षीय किशोर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान लोकेश्वर देवांगन (17 वर्ष) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, रात में खाना खाने के बाद लोकेश्वर अपने कमरे में चला गया था। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने तत्काल डायल-112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की से झांककर देखा तो किशोर फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। इसके बाद दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं की जांच जारी है।

प्रेमी की शादी से नाराज नाबालिग टॉवर पर चढ़ गई

जशपुरनगर। जिले के तुमला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजियाडीह गांव में बुधवार दोपहर को एक नाबालिग लड़की मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। नाबालिग करीब दो घंटे तक टॉवर के ऊपर बैठी रही, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास और लगातार समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग कोल्हनझरिया गांव की निवासी बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि वह अपने प्रेमी की शादी से नाराज थी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 और तुमला पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने युवती से लगातार बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। करीब दो घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान लोगों की निगाहें टॉवर पर टिकी रहीं। काफी देर तक चली समझाइश, संवाद और भरोसा दिलाने के बाद युवती आखिरकार टॉवर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुई।

साइबर ठगी के लिए म्यूल अकाउंट का उपयोग, दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में आए 6 शातिर, भेजे गए जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। साइबर ठगी की रकम के लेनदेन के लिए म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल एवं प्राप्त साइबर शिकायतों के परीक्षण में म्यूल खातों का उपयोग होना पाया गया। आरोपियों के बैंक खातों में लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अनाधिकृत ट्रांजेक्शन पाए गए। दुर्ग पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना उतई क्षेत्रांतर्गत संचालित **IDFC First Bank** के खातों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न साइबर ठगी प्रकरणों में प्रयुक्त रकम कुछ संदिग्ध खातों में प्राप्त हुई थी, जो म्यूल खातों की श्रेणी में आते हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के मध्य इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त राशि को प्राप्त कर अन्य खातों में स्थानांतरित एवं आहरित किया गया, जिससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। जांच उपरांत 30 संदिग्ध खाताधारकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 246/2026 धारा 318(2), 318(3), 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान बैंक से प्राप्त केवाईसी, खाता विवरण एवं ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया, जिसमें आरोपियों के खातों में लाखों रुपये के अनाधिकृत लेन-देन पाए गए। आरोपियों की पहचान कर दिनांक 16.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड एवं मोबाइल सिम अन्य व्यक्तियों को साइबर ठगी से संबंधित अवैध आर्थिक लेन-देन के लिए उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया। इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ था। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में एसीसीयू टीम एवं थाना उतई से सउनि सुरेश पाण्डेय, आरक्षक जी.जगमोहन एवं महिला आरक्षक बिन्दु भाले की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाइल सिम अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी उपयोग हेतु उपलब्ध न कराएं ऐसा करना साइबर अपराध में सहभागिता माना जा सकता है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

- भूपेन्द्र हिरवानी पिता रितेश हिरवानी उम्र 23 वर्ष पता पॉच रास्ता, मोतीलाल चैक, बजरंग बली मंदिर के पास थाना सुपेला जिला दुर्ग।
- नवलेश्वर पाटले पिता ओमकार पाटले उम्र 35 वर्ष पता डॉक्टर जी.के. वर्मा क्लीनिक के पास, वार्ड 06, संजय नगर, थाना सुपेला जिला दुर्ग।
- पवन सिंह पिता अमीर सिंह उम्र 32 वर्ष पता भाई किराना दुकान के पास, प्रगति नगर, केम्प 01, जलेबी चैक, भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग।
- आकाश चन्द्राकर पिता आशाराम चन्द्राकर उम्र 37 वर्ष पता कृष्णा टाकीज के सामने, मैत्रीनगर, फेस 04, रिसाली थाना नेवई जिला दुर्ग।
- अर्पण शुक्ला पिता ऋषिकुमार शुक्ला उम्र 23 वर्ष पता हाउस नंबर 770, इंडोर स्टेडियम पास, हनुमान मंदिर, तितुरडीह, दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग।
- मुकेश सिंह पिता दिलीप सिंह उम्र 23 वर्ष पता क्वाटर नंबर 28सी, सड़क 37सी, सेक्टर 07 भिलाई थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग।

22 साल की शादीशुदा महिला ने फांसी लगाई, जांच जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 22 साल की शादीशुदा महिला ने फांसी लगा ली है। फंदे पर लटकने से लेकर मौत तक मोबाइल में लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। जब उसकी सास घर आई, तब इसका पता चला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस को महिला के मोबाइल से करीब डेढ़ घंटे का एक वीडियो मिला है, जिसमें वह खुद फंदे पर झूलती नजर आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि, महिला सोशल मीडिया के लिए 'रील' बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हादसा हो गया। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

मृतका के पति शुभम देवांगन (22 साल) के मुताबिक काम से लौटे तो घटना के बारे में पता चला। विशाखा रील बनाने की शौकीन थी और इंस्टग्राम में अपलोड करती थी। उसने बताया कि दोनों 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं और उनके बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद भी नहीं हुआ था।

जानिए क्या है पूरा मामला ? कोष्टापारा निवासी विशाखा देवांगन (22) की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। उसका पति शुभम देवांगन जूता चप्पल की दुकान में काम करता है। मंगलवार दोपहर वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसकी सास घर लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो विशाखा साड़ी के फंदे से पंखे पर लटकी हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को मृतिका का मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग मोड में मिला। जांच में मोबाइल से करीब डेढ़ घंटे का वीडियो बरामद हुआ है। वीडियो में विशाखा पंखे पर साड़ी बांधकर फंदा तैयार करती दिखाई दे रही है। कुछ सेकंड बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह फंदे पर झूलने लगती है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि वह खुद को बचाने के लिए फंदा काटने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाती।

बुजुर्ग महिला की मलगेर नदी में डूबने से मौत

सुकमा। सुकमा जिले के गादीरास थाना क्षेत्र में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला की नदी में डूबने से मौत हो गई। मलगेर नदी पार करने के दौरान हुए इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला चुले कवासी (65) गुरुवार सुबह बैंक से 7 हजार निकालकर अपने गांव वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाली मलगेर नदी को पार करते समय वह गहरे पानी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, उसके घर तमिया पारा से बैंक शॉर्टकट में 2 किमी की दूरी पर है। जबकि पुल से जाने 6 किमी दूर पड़ता है। नदी में ज्यादा पानी नहीं होने के कारण वो शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल कर रही थी।

भिलाई में परिवार पर जानलेवा हमला 3 नाबालिग सहित 8 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात को परिवार पर तजानलेवा हमला करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा एवं धारदार हथियार बरामद कर जब्त किया गया। प्रकरण में 05 आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया तथा 3 नाबालिग आरोपियों पर अलग से कार्रवाई की गई है।

बता दें मंगलवार की रात लगभग 8:00 बजे दीपक साहू के परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान संतु मारकण्डेय, सतीश मारकण्डेय एवं दीपक साहू के साथ गाली-गलौज कर डंडा एवं धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। घटना में गर्भवती महिला भी घायल हो गई। रिपोर्ट पर थाना जामुल में धारा 296, 351(3), 109(1), 191(2), 191(3), 3(5) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों की पहचान हर्ष साहू, दिनेश साहू उर्फ दीनू, विजय यादव उर्फ करण यादव, परिचय उर्फ गुलशन, मोह. आसिफ आदि के रूप में हुई।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों की तलाश की गई। मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व विवाद के कारण घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा एवं धारदार हथियार बरामद कर जप्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना जामुल पुलिस की टीम, विवेचना अधिकारी एवं स्टाफ की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सराहनीय रही, जिनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कानून सम्मत एवं शांतिपूर्ण तरीके से करें। कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

आरोपियों के नाम

- हर्ष साहू उर्फ अंशु साहू, उम्र 18 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल।
- दिनेश साहू उर्फ दीनू, उम्र 40 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल।
- विजय यादव उर्फ करण यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल।
- परिचय उर्फ गुलशन यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल।
- मोह. आसिफ उम्र 22 वर्ष, निवासी बाम्बे आवास घासीदास नगर जामुल।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
(संपत्तिकर विभाग)

कमांक/चार/तीन/सं.क.वि./2026/ 145/104 — भिलाई, दिनांक 15/06/2026

//स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना//

इस ईश्तहार द्वारा हित रखने वाले हितग्राही को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 में स्वत्वाधिकार के अंतरण के संबंध में निम्नलिखित हस्तांतरिती के नाम से जिसका कि नगर पालिक निगम भिलाई के संपत्तिकर अभिलेख में हस्तांतरणकर्ता के स्थान पर नाम दर्ज किया जाना है यदि किसी को इस संबंध मे कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरकार्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है बाद मे प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा:-

क्र.	हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरिती का नाम	हस्तांतरण का स्वरूप	संपत्ति की स्थिति
1.	श्रीमती आर. परमेश्वरी, ध.प. श्री एन.राजू, से 1. श्रीमती सरिता अग्रवाल, ध.प. श्री रामऋषि अग्रवाल, निवासी- शॉप नं.- 59, सी. मार्केट, सेक्टर-1, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.), 2. श्रीमती बीना अग्रवाल, पति- श्री अनिल अग्रवाल, 3. श्रीमती राखी अग्रवाल, पति- श्री सतीश अग्रवाल, दोनों निवासी- 66/A, वार्ड-12, सुंदर नगर, सुपेला भिलाई, तह. व जिला - दुर्ग(छ.ग.) तीनो के तरफ से आम मुख्त्यार- रामऋषि अग्रवाल, पिता- ब्रम्हानंद अग्रवाल, निवासी- शॉप नं.- 59, सी. मार्केट, सेक्टर-1, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती प्रीति रणनवरे, पति- सचिन राव रणनवरे, निवासी- 71, टाटा लाईन बसंत टॉकीज के पास, केम्प-2, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	बिक्रीनामा	कोहका, (वार्ड नं.- 14, राम नगर वार्ड के बाबा दीप सिंह नगर अंदर भाग में स्थित), खसरा नं.- 8105, रकबा- 1925 वर्गफीट, आवासीय रिक्त भूमि।
2.	मनोरमा बानोकर पति - मधुकर बानोकर, निवासी- हाउस नं.- 1488, स्ट्रीट नं.- 02, शिवाजी नगर कोहका, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	तरूण कुमार बनोकर, पिता - मधुकर बनोकर, निवासी- हाउस नं.- 1488, अवंती बाई चौक, शिवाजी नगर कोहका, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	दानपत्र	कोहका, (वार्ड नं.- 09, पुरानी बस्ती कोहका वार्ड के शिवाजी नगर अंदर भाग) खसरा नं. - 6758/1, रकबा- 1106 वर्गफीट, आवासीय भवन निर्मित।
3.	शुभोदीप मुखर्जी, पिता - शांतिमय मुखर्जी, निवासी- 279 टी.वी. टावर रोड वार्ड नं.- 04 आमाखेरवा मनेन्द्रगढ कोरिया (छ.ग.)	संजय कुमार डोंगरे पिता- विनायक डोंगरे, निवासी- चरोदा बस्ती के पास C.S.E.B. 10 वार्ड नं.- 19 भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	बिक्रीनामा	जुनवानी वार्ड नं.- 01, चौहान ग्रीन वैली एवं चौहान के अन्य हाउसिंग मकान/अपार्टमेंट अंतर्गत अन्दर भाग भिलाई, फ्लैट नं.- 12, ब्लॉक-A1, तृतीय तल, क्षेत्रफल- 595.00 वर्गफीट, आवासीय फ्लैट निर्मित।
4.	श्री विपुल कटारिया, पिता- श्री प्रकाश भाई कटारिया, निवासी- म.नं. - 20, श्री श्याम वाटिका, सड़क- 25, स्मृति नगर, महर्षि विद्या मंदिर के पीछे, भिलाई तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)	श्री राकेश कुमार करांगले, पिता- स्व. प्रभाकर गोपाल करांगले, निवासी- रिलायंस टावर के पास, शिक्षित नगर, वार्ड - 23, चरोदा, भिलाई, तह. भिलाई-3, जिला- दुर्ग(छ.ग.)	बिक्रीनामा	स्मृति नगर वार्ड नं.- 02, के अंतर्गत आनंद नगर अंदर भाग (श्याम वाटिका, महर्षि स्कूल के पीछे) खसरा नं.- 351/8, रकबा- 1030 वर्गफीट, आवासीय भवन निर्मित।
5.	श्रीमती पुष्पा दुबे पति श्री सुरेश चंद दुबे, निवासी- सुन्दर विहार कॉलोनी नालंदा ई एम विद्यालय के पास कुरूद, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	श्रीमती वेंकट लक्ष्मी पति श्री के.एस. राजन, निवासी- ई.डब्ल्यू.एस.- 1665, वार्ड नं.- 16, हाउसिंग बोर्ड, आई ई, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	बिक्रीनामा	कुरूद, वार्ड नं.- 16, कुरूद वार्ड, भिलाई (सुन्दर विहार अंदर भाग), खसरा नं.- 1427/74 शामिल खसरा नं.- 1428/74, 1429/74 व 1433/74, क्षेत्रफल- 1050 वर्गफीट, आवासीय भवन निर्मित।
6.	श्रीमती वर्षा सोनी, पति-अशोक सोनी, निवासी- के पी एस स्कूल के पास वार्ड नं.- 12 सुन्दर नगर सुपेला भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	कमलजीत वर्मा, पिता- स्व. श्याम लाल वर्मा, निवासी- मकान नं.- 112 वार्ड नं. - 09, अम्बेडकर नगर राम नगर सुपेला भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)	बिक्रीनामा	कोहका, वार्ड नं.-20 वैशाली नगर वार्ड के गौरव पथ मार्ग (राम नगर चौक से मुक्ति धाम रोड मोड पर गुरूनानक मार्केट) खसरा नं.- 8680/6 एवं 8680/7, रकबा- 180 वर्गफीट एवं 300 वर्गफीट, कुल रकबा- 480 वर्गफीट, भवन निर्मित।
7.	चौहान हाउसिंग प्रा.लिमि. जुनवानी, डायरेक्टर श्री अजय चौहान आ. स्व. श्री विपत(दीपेश्वर) चौहान, मोहल्ला/गांव/ कालोनी:- राजीव नगर, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग(छ.ग.)	श्रीमती अभिलाषा भट्ट ध.प. श्री ए.के. भट्ट, मोहल्ला/गांव/कालोनी:- क्वा. नं.-3A, स्ट्रीट नं.-17, सेक्टर-10, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग(छ.ग.)	बिक्रीनामा	वार्ड नं.- 01, चौहान हाउसिंग प्रा.लिमि., सी. एच.पी.एल. चौहान टाउन, जुनवानी रोड भिलाई, फ्लैट नं. - 18 (द्वितीय तल), ब्लॉक नं.- सी2, क्षेत्रफल- 969.26 वर्गफीट, आवासीय फ्लैट निर्मित।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

25-30 साल की महिला की गला रेतकर हत्या

महासमुंद। ग्राम तुरेंगा में बुधवार सुबह खेत में 25 से 30 साल की अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक शव तुरेंगा निवासी खेमसिंह दीवान के खेत में मिला। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में चोट के निशान साफ दिखे। किसी अज्ञात आरोपी ने महिला के गले, दाढ़ी, जबड़े पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। मृतका का रंग गोरा है। चेहरा गोल है। कद करीब 5 फीट है। उसने नीले रंग का गाउन, कत्थई रंग का पेटीकोट, संतरा रंग की चुनरी पहनी है। दोनों हाथों में हरे रंग की चूड़ियां हैं। कत्थई रंग का कंगन है। गले में लाल रेशमी धागे का मंगलसूत्र है। पैरों में पायल, बिछिया हैं।

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sis Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

खास खबर

पहाड़ी कोरवाओं के सर्वेक्षण के लिए दिया गया विशेष प्रशिक्षण

रायगढ़। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों के समग्र विकास और शासन की योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत लैलूंगा के सभा कक्ष में मंगलवार को पहाड़ी कोरवा परिवारों के हाउसहोल्ड डाटा कैप्चर कार्य हेतु गठित सर्वे दलों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वे दलों को मोबाइल आधारित सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से परिवारों की जानकारी संकलित करने, दस्तावेजों के सत्यापन, पात्रता निर्धारण तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के संतृप्तिकरण संबंधी जानकारी विस्तार से प्रदान की गई।

कौशल प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग पार्टनर से आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए ट्रेनिंग पार्टनर एवं प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। जारी सूचना के अनुसार इच्छुक एवं पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई शाम 5 बजे तक है, जबकि प्राप्त आवेदनों को 8 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से खोला जाएगा। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी ने बताया कि चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। https://raigarh.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट देख सकते हैं।

सोलर सेनेटरी किट से सूरजपुर की बेटी ने बनाई राष्ट्रीय पहचान, महिला स्वास्थ्य को समर्पित है प्रोजेक्ट

श्रीकंचनपथ समाचार

सूरजपुर। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करवां की छात्रा गीता सिंह द्वारा विकसित सोलर सेनेटरी किट आज नवाचार और सामाजिक सरोकार का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है। उसके इस किट को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी दिशा में छात्रा गीता सिंह ने यह मॉडल पेश कर सूरजपुर जिले का नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।

एक हजार रुपये से भी कम लागत में तैयार इस मॉडल का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बेहतर बनाना है। छात्रा द्वारा विकसित सोलर सेनेटरी किट का उपयोग सेनेटरी पैड अथवा अन्य उपयोगी कपड़ों को प्रयोग से पूर्व जीवाणुमुक्त करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा आधारित यह उपकरण बैक्टीरिया को नष्ट कर संक्रमण की

संभावनाओं को कम करने में सहायक है। विशेष रूप से माहवारी एवं प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए यह नवाचार अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चूंकि यह उपकरण सौर ऊर्जा का उपयोग करता है इसलिए पर्यावरण हितैषी भी है। इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी सहजता से किया जा सकता है।

गीता सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छता संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक छात्रा और महिला होने के नाते उन्होंने इस समस्या को नजदीक से देखा और इसके समाधान के लिए यह मॉडल विकसित किया। उनके इस अभिनव प्रयास को राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी इस मॉडल ने द्वितीय स्थान हासिल कर विशेष पहचान बनाई है। छात्रा ने बताया कि उनके इस नवाचार में अन्य राज्यों की भी रुचि बढ़ रही है। कर्नाटक सहित रायपुर के एक विद्यालय द्वारा इस मॉडल को अपने यहां स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को

स्वस्थ जीवन के लिए योग थीम पर अभ्यास करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधि

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। 21 जून 2026 को इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री द्वय, मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण मुख्य अतिथि होंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास में मुख्य अतिथि नामांकित किया गया है।

राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में 21 जून को राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे।

जारी आदेश के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि होंगें। इसी प्रकार कोरिया जिले में मंत्री रामविचार नेताम, महासमुंद जिले में मंत्री दयालदास बघेल, सुकमा जिले में मंत्री केदार कश्यप, कांकेर जिले में मंत्री लखन लाल देवांगन, जांजगीर-चांपा जिले में मंत्री ओपी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मंत्री टंकराम वर्मा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जशपुर जिले में मंत्री राजेश अग्रवाल, कोरबा जिले में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और बालोद जिले में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बनाए गए हैं।

विभिन्न जिलों में योग दिवस के गरिमामय आयोजन की कमान माननीय सांसदों और विधायकों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा जिले में सांसद विजय बघेल, मोहला-मानपुर-चौकी जिले में सांसद संतोष पांडेय 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार सूरजपुर जिले में सांसद चिंतामणी महाराज, गरियाबंद जिले में सांसद रूपकुमारी चौधरी, रायगढ़ जिले में सांसद राधेश्याम राठिया, जांजगीर जिले में सांसद कमलेश जांगड़े, नारायणपुर जिले में सांसद महेश कश्यप और कोण्डागांव जिले में सांसद भोजराज नाग 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। बीजापुर जिले में विधायक लता उसेंडी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में विधायक ललित चंद्राकर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, मुंगेली जिले में विधायक पुन्नूलाल मोहले, धमतरी जिले में विधायक अजय चंद्राकर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, बस्तर जिले में विधायक किरण सिंह देव और दंतेवाड़ा जिले में विधायक चौतराम अटामी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाए गए हैं।

नवा रायपुर जंगल सफारी में दिखा सबसे छोटा कठफोड़वा

- बॉटेनिकल गार्डन में ब्राउन-कैप्ड पिग्मी वुडपैकर की दुर्लभ मौजूदगी दर्ज'
- जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मिली नई पहचान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के बॉटेनिकल गार्डन में पक्षी प्रेमियों और प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए एक सुखद समाचार सामने आया है। हाल ही में आयोजित बर्ड वॉक के दौरान वन्यजीव छायाकारों ने भारत के सबसे छोटे कठफोड़वों में से एक ब्राउन-कैप्ड पिग्मी वुडपैकर को कैमरे में कैद किया। तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में इस दुर्लभ पक्षी की मौजूदगी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में नवा रायपुर का जंगल सफारी और बॉटेनिकल गार्डन जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यहां विकसित हरित वातावरण और संरक्षण उपायों के कारण अनेक पक्षी एवं वन्यजीवों को सुरक्षित आवास मिल रहा है।

ब्राउन-कैप्ड पिग्मी वुडपैकर भारत के सबसे छोटे कठफोड़वों में शामिल है। इसकी लंबाई लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर होती है। यह पक्षी पेड़ों की छाल पर बेहद फुर्ती से चढ़ता-उतरता है और अपनी विशिष्ट गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसके सिर पर भूरे रंग का मुकुटनुमा भाग तथा शरीर पर काले-सफेद धब्बेदार पंख होते हैं, जो इसे आकर्षक और आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं।

बैटरी कबाड़ियों पर पर्यावरण मंडल सख्त बिना पंजीयन के नहीं कर पाएंगे व्यवसाय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्य में अवैध रूप से स्क्रैप एवं प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) तथा व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडल ने सभी व्यापारियों, कबाड़ संचालकों, स्क्रैप डीलरों, परिवहनकर्ताओं तथा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हितधारकों को निर्देशित किया है कि वे अपना संचालन केवल बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 एवं अन्य प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही करें।

मंडल के संज्ञान में आया है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बिना आवश्यक पंजीयन, प्राधिकार एवं वैध दस्तावेजों के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा क्रय-विक्रय किया जा रहा है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं तथा पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हैं।

मंडल ने बताया कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत प्रयुक्त एवं अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अपशिष्ट बैटरियों के परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन तथा आवश्यक दस्तावेजों का संधारण अनिवार्य है। इसके साथ ही खरीद-बिक्री संबंधी अभिलेख एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण, पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालन अथवा अवैध व्यापार दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में राज्यभर में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, फर्मों एवं संस्थानों के विरुद्ध जांच, निरीक्षण तथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी संबंधित हितधारकों से अपने संचालन को तत्काल प्रभाव से नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने तथा आवश्यक पंजीयन एवं अनुमतियां प्राप्त करने का आग्रह किया है।

खेलो इंडिया सेंटर सूरजपुर की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, आवासीय खेल अकादमी के लिए हुआ चयन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में जिला सूरजपुर के खेलो इंडिया सेंटर हराटिकरा की एक प्रतिभावान बालिका खिलाड़ी का चयन आवासीय खेल अकादमी रायपुर के लिए हुआ है। यह उपलब्धि न केवल सूरजपुर जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

ग्रामीण अंचल से निकलकर अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण के बल पर बालिका खिलाड़ी ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उसके चयन से यह साबित हुआ है कि उचित मार्गदर्शन, नियमित प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर प्रदेश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने बालिका खिलाड़ी को फुटबॉल भेंट कर सम्मानित किया तथा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जिले की बेटियां खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और अपनी उपलब्धियों से अन्य बच्चों को भी प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने खिलाड़ी को निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेलो इंडिया सेंटरों के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं और युवा खिलाड़ी राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना रहे हैं।

बालिका खिलाड़ी के चयन से जिले में हर्ष का माहौल है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं अभिभावकों ने इसे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताते हुए खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर खेल अधिकारी श्रीमती आरती पांडेय तथा खेलो इंडिया सेंटर हराटिकरा के प्रशिक्षक श्री प्रकाश गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर पंचायत शिवनंदनपुर के शपथ ग्रहण में बोले मुख्यमंत्री

जनसुविधाओं के लिए समर्पण के साथ काम करें जनप्रतिधि

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान नवनिर्मित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष रितेश जायसवाल सहित सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए जनसेवा और विकास के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने नगर पंचायत शिवनंदनपुर के वार्ड क्रमांक 06 में सुसज्जित मंगल भवन निर्माण की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर उपस्थित नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलना क्षेत्र की वर्षों पुरानी आकांक्षा की पूर्ति है। इससे क्षेत्र में सुनियोजित नगरीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि

जनता ने जिस विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों का चयन किया है, उस विश्वास पर खरा उतरना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच सेतु बनकर जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने तथा अपने अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। सरकार जनता की समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि शिवनंदनपुर के नगर पंचायत बनने से क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शिवनंदनपुर में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों और दूरदर्शी सोच के कारण शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह क्षेत्र के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधाएं और विकास कार्यों का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी एवं जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 जुलाई तक करें आवेदन

श्रीकंचनपथ समाचार

बेमेतरा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष इसके लिए आवेदन दिनांक 31 जुलाई 2026 तक केवल ऑनलाइन लिये जायेगें। जिले से उक्त संबंध में आवेदन ऑनलाईन भरा जाना है। भारत सरकार का महिला एंव बाल विकास मंत्रालय असाधारण क्षमताओं वाले बच्चों को उचित मान्यता देने के लिए हर साल प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आयोजित करता है यह पुरूस्कार वीरता सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में माननीय

राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिये जाते है। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्राप्त करने का पोर्टल (https://awards.gov.in) 01.04.2026 को लाइव कर दिया गया है। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष (संबंधित वर्ष की 31 जुलाई को 2026) से अधिक नहीं है, जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। पीएमआरबीपी के लिए आवेदन केवल इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाईन पोर्टल https://awards.gov.in पर प्राप्त किए जाएगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.07.2026 है। पीएम-आरबीपी पुरस्कार उन युवा बहादुरों को प्रदान किए जाते है जिन्होंने दूसरों के लिए असाधारण बहादुरी के निस्वार्थ कार्य किए है और असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले छोटे बच्चों को प्रदान किया जाता है। जो रोल मॉडल है और जिनका व्यापक और दृश्य प्रभाव पडा है। खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण, कला और संस्कृति एवं नवाचार के क्षेत्र में समाज में जो राष्ट्रीय स्तर पर उचित मान्यता के योग्य है, उन्हें वीरता पुरस्कार एंव उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950